● वर्ष-2
● अंक-187
रायपुर, बुधवार
29 मार्च 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmailÐcom

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

संसद ठपः आर-पार के मूड में विपक्ष

लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ ला सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव

नई दिल्ली। लोकसभा से राहुल गांधी की अयोग्यता के बाद विपक्षी दल लामबंद दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी दल जबरदस्त तरीके से भाजपा और केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस इसे लेकर आर-पार के मूड में नजर आ रही है। इन बस के बीच कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्षी दलों से बात करने की योजना बनाई है। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस सांसदों की एक बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया था। इसके अलावा, इसने कहा कि कांग्रेस अन्य दलों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है। हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई क्यों कर रही है।

फिलहाल खबर जो आ रही है उसके मुताबिक विपक्षी दल लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ सोमवार यानी कि 3 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई। पार्टी के लोकतंत्र को बचाने के महीने भर के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को कहा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना सहित 19 विपक्षी दल कांग्रेस के साथ हैं। आपको बता दें कि 2019 के मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा ने विपक्षी दलों को एक साथ ला दिया क्योंकि गैर-कांग्रेसी दलों ने सजा को राजनीति से प्रेरित बताया है। सजा के तुरंत बाद, राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसी के बाद विपक्षी एकता दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने की कोई बातचीत नहीं हुई क्योंकि लोकतंत्र को बचाना प्राथमिक उद्देश्य है।

संविधान बचाने का अंतिम चुनाव- अखिलेश

विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ हमला तेज कर दिया है। 11 अन्य दलों ने सोमवार को भारतीय

जनता पार्टी (भाजपा) से लड़ने का संकल्प लिया और विपक्षी नेताओं को चुप कराकर 'लोकतंत्र की हत्या' करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये बड़ी साजिश है। सभी स्थानीय पार्टियां भाजपा का लगातार मुकाबला कर रही हैं। भाजपा का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस या अन्य दल स्वतंत्र हैं कि वो किसके साथ खड़े होंगे। 2024 में गठबंधन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कानपुर में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि 2024 में भाजपा का सफाया होगा। आज जो गठबंधन दल समाजवादी पार्टी के साथ हैं, हम उनके साथ ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ हमला तेज करते हुए एक दिन पहले यानी 27 मार्च को 'लोकतंत्र के लिए काला दिवस' मनाया।

अडानी समूह में पैसा मोदी का -केजरीवाल

नई दिल्ली। अडानी मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर ईडी या सीबीआई जांच हिडेनबर्ग रिपोर्ट को लेकर होती है, तो मोदी जी नीचे जाएंगे, अडानी नहीं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, %प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी के लिए कुछ नहीं किया, फिर वह अपने दोस्त के प्रति इतने दयालु क्यों हैं? इतना बड़ा संकट आया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई... मोदीजी अडानी को बचाने में लगे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि अडानी सिर्फ सामने है; उनके पीछे निवेशक मोदी हैं। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने अडानी समूह को 442 मिलियन की पवन ऊर्जा परियोजना देने के लिए श्रीलंका पर दवाब बनाया। मोदीजी ने श्रीलंका को अडानी को पवन परियोजना देने के लिए मजबूर किया।

ओबीसी समुदाय को साधने भाजपा का चलेगा अभियान

राहुल प्रकरण को राजनीतिक लाभ में तब्दील करने के लिए भाजपा ने ओबीसी समुदाय की साधने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। ओबीसी समुदाय को साधने के लिए पार्टी छह अप्रैल से 14 अप्रैल तक गांव-गांव चलो, घर-घर चलो अभियान शुरू करने जा रही है। इसके अंतर्गत देश के एक लाख गांवों के एक करोड़ ओबीसी समुदाय के घरों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान पार्टी सरकार के द्वारा ओबीसी समुदाय के लिए किए गए कार्यों की जानकारी देगी। साथ ही वह राहुल गांधी के बयान पर भी निशाना साधेगी। भाजपा नेता के. लक्ष्मण ने कहा कि पार्टी का ओबीसी मोर्चा देश के एक लाख गांवों में एक करोड़ परिवारों तक पहुंचेगा। इस बीच डॉक्टर आंबेडकर जयंती और पार्टी स्थापना दिवस को भी मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उस दौरान जनता को यह बताने की कोशिश रहेगी कि केंद्र में भाजपा सरकार के नौ साल में ओबीसी समुदाय के लिए सरकार ने क्या किया गया। इस अभियान की शुरुआत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा से करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार आने के बाद ओबीसी समुदाय के अलग-अलग वर्गों को लक्ष्य बनाकर उनके विकास की योजनाएं बनाई गई हैं।

इन दिनों — शशांक शर्मा

विधानसभा चुनाव का माहौल बनने लगा

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के बाद प्रदेश में चुनावी माहौल बनने लगा है। वैसे तो प्रदेश भर में पिछले कुछ महीनों के दौरान कांग्रेस-भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों के संभावित दावेदार दीवारों पर अपने नाम की पेटिंग करना प्रारंभ कर चुके हैं। राजनीतिक पार्टियां भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी की प्रभारी कुमारी शैलजा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक लेने प्रदेश आई हुई हैं, वहीं भाजपा भी अब सड़क की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है। जैसे-जैसे चुनाव करीब आता है, अगली सरकार किसकी बनेगी, इसकी कयास लगाने का सिलसिला भी शुरु हो जाता है। साथ ही साथ मीडिया हाउस ओपनियन पोल करवाकर माहौल को और गर्म करते हैं। अभी एक इलेक्ट्रानिक मीडिया ने अपने ओपनियन पोल में बताया कि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को जीत मिल सकती है। अपने ओपनियन पोल के जरिए उक्त समाचार चैनल का मानना है कि कांग्रेस पार्टी को 49 से 54 सीटें मिल सकती है और भाजपा को 37 से 42 सीटें मिलने की संभावना है। इस ओपनियन पोल में सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा यह बताया गया कि कांग्रेस का मत प्रतिशत 44 होगा और भाजपा का मत प्रतिशत 43 होगा। 2018 के चुनाव से अगर तुलना करें तो भाजपा को 32.97 प्रतिशत वोट मिले थे और कांग्रेस पार्टी को 43.04 वोट मिले थे। इस प्रकार वोट का अंतर 10 प्रतिशत से अधिक था। अगर इसे संख्या में ले तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में 14 लाख 37 हजार मतों का अंतर है। इस स्थिति में भाजपा के पास अभी 14 विधायक हैं और कांग्रेस के पास 71। इसका मतलब है कि अगर भाजपा ओपनियन पोल के मुताबिक 43 प्रतिशत मत पा सकती है तो यह भाजपा के लिए अच्छी खबर हैं। वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का मत भी 1 प्रतिशत बढ़ रहा है। इसका दूसरा मायने यह है कि इस आगामी चुनाव में जनता ने अपनी राय केवल भाजपा और कांग्रेस को ध्यान में रखकर दी है। पिछले चुनाव में जोगी कांग्रेस-बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और अकेले जोगी कांग्रेस ने 10 लाख 86 हजार मत प्राप्त किए थे। यही वोट कांग्रेस और भाजपा के बीच में बट रहा है। भाजपा-कांग्रेस के बीच में अगर मतों को अंतर कम हुआ है तो इसका मतलब भाजपा के परंपरागत वोटर फिर से एकजुट हुए हैं। वहीं, कांग्रेस सरकार के मंत्री एवं जनप्रतिनिधि के खिलाफ भी जनमत तैयार हुआ होगा। वैसे तो ओपनियन पोल कुछ हजार लोगों से बातचीत करके तैयार किए जाते हैं, लेकिन प्रदेश में जो राजनीतिक वातावरण दिख रहा है, उससे अगले चुनाव में रोचक होना की संभावना बढ़ गई है। अगले कुछ महीनों में राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ेगी।

बिजली दर में कोई बढ़ोत्तरी नहीं, कंपनी का घाटा बढ़ा

रायपुर। चुनावी साल में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। किसी भी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। राज्य बिजली नियामक आयोग की तरफ से जारी नये वित्तीय वर्ष की टैरिफ दर में ।ङ्क-5 एवं स्ङ्क-5 श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले पोहा एवं मुरमुरा मिल को ऊर्जा प्रभार में 5 प्रतिशत की छूट को जारी रखा गया है। वहीं उच्च दाब उद्योगों के विद्युत प्रदाय वोल्टेज के अनुसार लागू दरों में अंतर को ध्यान में रखते हुए. 220 द्मङ्क एवं 132द्मङ्क के उच्च दाब स्टील उद्योगों के दरों को युक्तिसंगत किया गया है।1 अप्रैल, 2023 से प्रभावशील होंगी।

विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि घरेलू, कृषि और लघु उद्योगों की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तीनों श्रेणियों के विद्युत दरों में इस साल कोई बढ़ोतरी नही की गयी है। उच्च ताप वाले स्टील उद्योगों की दरों में 25 पैसे की बढ़त, 220 चङ्क और 132 चङ्क सप्लाई में 25 पैसे की वृद्धि, लघु और बड़े उद्योग को मिलने वाली छूट बरकरार रहेगी। ऑक्सीजन प्लांट को दी गई 10 प्रतिशत छूट वापस ली गई है, वहीं ग्रामीण उद्योगिक पार्क को निम्न श्रेणी में रख कर राहत दी गयी है।

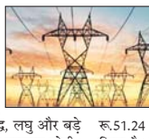

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी ने वर्ष 2021-22 हेतु रू.538,04 करोड़ राजस्व घाटे की मांग की है जिसे आयोग ने मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी ने विगत वर्षों के रू.38.22 करोड़ के राजस्व घाटे की मांग की थी परंतु आयोग ने इसके स्थान पर रू.51.24 करोड़ राजस्व घाटे का अनुमोदन किया है। वर्ष 2021-22 के घाटे और वर्ष 2023-24 के लिए बिजली की अनुमानित बिक्री पर प्रचलित टैरिफ से अनुमानित राजस्व के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी (सीएसपीडीसीएल) ने रू. 2950.54 करोड़ राजस्व घाटे का दावा किया है। संपूर्ण विश्लेषण के उपरान्त आयोग ने रू. 2950.54 करोड़ के घाटे के स्थान पर रू.2924.53 करोड़ को ही मान्य किया है। विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा मांग की गई वार्षिक राजस्व आवश्यकता रू.15581.14 करोड़ के स्थान पर रू. 17220.31 करोड़ गान्य किया गया है। उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयोग द्वारा आकलित औसत विद्युत लागत दर रु.6.58/- निर्धारित होती है। प्रचलित दरों के आधार पर वर्ष 2023-24 की आकलित औसत विद्युत बिलिंग दर रू .0.21 होती है।

प्रमुख समाचार

केंद्रीय मंत्री पर हमले के मामले में सीबीआई करे मामले की जांच-कलकत्ता हाईकोर्ट

कोलकाता। केंद्रीय मंत्री निसिथ प्रमाणिक के काफिले पर हुए हमले के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई जांच का आदेश

दिया है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीर बताते हुए इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की बात कही। गौरतलब है कि इसी साल फरवरी में गृह-युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक के काफिले पर कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) समर्थकों ने हमला किया था। मंत्री कूचबिहार के दिनहाटा इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे थे। मंत्री के काफिले पर उस समय हमला किया गया जब वह एक कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे थे। संपर्क किए जाने पर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हमले में भाजपा के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। टीएमसी समर्थकों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, जिसके बाद दोनों दलों के समर्थकों के बीच झड़पें शुरू हो गईं। सीसीटीवी फुटेज में दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो रही है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस लाठीचार्ज कर रही है।

ममता के धरने से पहले दिल्ली में बंगाल बीजेपी के सांसद, अब शाह करेंगे बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बंगाल के बीजेपी सांसदों से चर्चा नहीं होने की संभावना है।

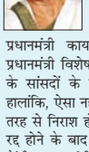

उनकी जगह बंगाल के सांसद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर पीएम मोदी ने बंगाल के बीजेपी सांसदों से मुलाकात को अचानक क्यों टाल दिया? प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री विशेष कारणों से मंगलवार रात बंगाल के सांसदों के साथ बैठक में नहीं आ पाएंगे। हालांकि, ऐसा नहीं है कि सुकांत मजूमदार को पूरी तरह से निराश होना पड़ा है। प्रधानमंत्री की बैठक रद्द होने के बाद गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों के साथ बातचीत करेंगे। सुकांत मंगलवार रात 9 बजे शाह से मिल सकते हैं। लंबे इंतजार के बाद सुकांतरा को मंगलवार को प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला। बैठक का मुख्य उद्देश्य मोदी को राज्य के मौजूदा हालात से अवगत कराना था। हालांकि, उनकी अभी प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं हो रही हैं।

24 घंटे में अमृतपाल के समर्थकों को रिहा करें, अकाल तख्त की धमकी

नई दिल्ली। अकाल तख्त ने अलगाववादी उपदेशक अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई को लेकर भगवंत मान सरकार और केंद्र के खिलाफ कड़ा बयान जारी किया है। अकाल तख्त की तरफ से सवाल किया गया है कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अलगाववादी उपदेशक के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पकड़े गए सिख युवकों को रिहा करने के लिए राज्य सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। वह पंजाब की स्थिति पर चर्चा करने के लिए बुद्धिजीवियों, वकीलों, पत्रकारों, धार्मिक और सामाजिक नेताओं सहित सिख संगठनों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। अकाल तख्त सिखों के लिए सत्ता की सर्वोच्च सीट है और इसके जत्थेदार उनके शीर्ष प्रवक्ता हैं। यह सवाल करते हुए कि कथित रूप से सिंह का समर्थन करने और उनकी खालिस्तान की मांग के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को क्यों लागू किया गया।

न्यायपालिका पर धनखड़, रिजिजू की टिप्पणी के खिलाफ कार्रवाई की मांग

मुंबई। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यायपालिका और कॉलेजियम प्रणाली पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ की टिप्पणियों के खिलाफ जनहित याचिका खारिज करने के उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वकीलों के निकाय ने बंबई उच्च न्यायालय के 9 फरवरी के आदेश को इस आधार पर खारिज करने के लिए चुनौती दी है कि यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं था। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने दावा किया था कि दोनों के उक्त बयान सर्वोच्च न्यायालय सहित संस्थानों पर हमला करके संविधान में विश्वास की कमी दिखा रहे हैं। इसने धनखड़ को उपाध्यक्ष के रूप में कर्तव्य का निर्वहन करने और रिजिजू को केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के आदेश भी मांगे थे। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन के वकील अहमद आब्दी ने दावा किया कि टिप्पणी न केवल संविधान के लिए अपमानजनक थी बल्कि बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करती थी और इससे अराजकता फैलती थी।

राजाताल पोस्ट पर मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन, हेरोइन और हथियार भी बरामद

चंडीगढ़। अमृतसर में बार्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने सोमवार रात अमृतसर सेक्टर में भारत

पाक सीमा स्थित बार्डर आब्जर्विंग पोस्ट (बीओपी) पर पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। अर्धसैनिक बल ने मंगलवार को कहा कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने प्रतिबंधित वस्तुओं की खेप लेकर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने के तुरंत बाद पंजाब में एक और पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। पंजाब के अमृतसर जिले में सोमवार रात करीब 8.20 बजे ड्रोन को मार गिराया गया, जब भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने उड़ने वाली वस्तु की आवाज सुनी। इसे मंगलवार सुबह सीमा सुरक्षा बल द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान बरामद किया गया। बीएसएफ कमांडेंट जसबीर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से आते एक ड्रोन को बीएसएफ के जवानों ने देखा उसे गिराया। हमने पुलिस के साथ मिलकर इलाके की घेराबंदी कर गहन खोज अभियान किया जिसमें एक व्यक्ति को हिरासत में लिया।

सांसदों, विधायकों के लिए कानून में बचाव जरूरी

कपिल सिब्बल

कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी के भाषण के कारण गुजरात के सूरत में एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने उन्हें दोषी ठहराया। आपराधिक मानहानि के मामले में उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई है। वह प्रक्रिया जिसने उन्हें दोषसिद्धि तक पहुंचाया और स्वयं दोषसिद्धि ने उन मुद्दों को उठाया है जिन्हें कानून और राजनीति दोनों के दृष्टिकोण से संबोधित करने की आवश्यकता है। इनमें से किसी भी मुद्दे पर विचार करने से पहले, आइए यह समझें कि राहुल गांधी ने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए क्या कहा था, "मेरा एक सवाल है। इन सभी चोरों के नाम में मोदी मोदी मोदी क्यों हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी... और हम थोड़ा और सर्च करें तो ऐसे कई और मोदी सामने आएंगे।" उन्होंने जो कहा, उसके लिए गुजरात के एक पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने 16 अप्रैल, 2019 को उन पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा चलाने का फैसला किया। लेकिन इस बयान को पूरे 'मोदी समुदाय' के अपमान के रूप में नहीं माना जा सकता है। राहुल गांधी ने केवल इतना पूछा कि उन सभी कथित 'चोरों' के नाम के साथ 'मोदी' क्यों जुड़ा हुआ है। नीरव मोदी और ललित मोदी सरकार के रडार पर हैं। दोनों ने भारत वापस नहीं आने का फैसला किया है। राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि हर मोदी चोर होता है। उन्होंने केवल इतना पूछा कि 'इन चोरों' के नाम के साथ 'मोदी' क्यों जुड़ा हुआ है। इस आधार पर कोई भी सजा कि राहुल गांधी ने पूरे 'मोदी समुदाय' को बदनाम किया है, संदेहास्पद है। इसके अलावा, ऐसा कोई पहचान योग्य 'मोदी समुदाय' नहीं है जो राहुल गांधी की बातों से नाराज हो। राहुल गांधी 24 जून 2021 को सूरत में सीजेएम की अदालत में पहली बार व्यक्तिगत रूप से अपना बयान दर्ज कराने के लिए पेश हुए थे। मार्च 2022 में शिकायतकर्ता ने अनुरोध किया

कि राहुल गांधी को फिर से तलब किया जाए। अदालत ने अनुरोध को खारिज करते हुए जोर देकर कहा कि शिकायतकर्ता मामले के गुण-दोष के आधार पर अदालत में अपना पक्ष रखे। दिलचस्प बात यह है कि शिकायतकर्ता ने उच्च न्यायालय का रुख किया और मुकदमे पर सुनवाई रुक गई। करीब एक साल तक मुकदमा रुका रहा। बाद में शिकायतकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका वापस ले ली। इसके तुरंत बाद, 27 फरवरी, 2023 को ट्रायल फिर से शुरू हुआ; इस बार एक और सीजेएम एच।एच। वर्मा के सामने। बीच में, राहुल गांधी एक विशेष व्यवसायी को निशाना बना रहे थे, जो एक व्यवसायी के रूप में अपने अभूतपूर्व उत्थान के लिए विवाद का विषय बन गया है, और उनकी कंपनियों ने जो धन अर्जित किया है, वह कथित तौर पर प्रधानमंत्री से उनकी निकटता के कारण है। 8 मार्च 2023 को, राहुल गांधी के वकील ने पूर्णेश मोदी के अभियोग को चुनौती दी, यह दावा करते हुए कि राहुल गांधी के आपत्तिजनक भाषण ने व्यक्तियों को लक्षित किया न कि तथाकथित 'मोदी समुदाय' को। उच्च न्यायालय में कार्यवाही की त्वरित वापसी, मुकदमे की बहाली, कार्यवाही का समय और मामले की अचानक सुनवाई सवाल उठाती है, जिसका समय आने पर शायद जवाब मिल सके। राहुल गांधी गुजरात में नहीं रहते हैं। इसलिए आपराधिक मानहानि, अगर होती भी है तो कर्नाटक में दायर की जानी चाहिए। पूर्णेश मोदी ने सूरत को शायद इस उम्मीद से चुना था कि वे सीजेएम को राहुल गांधी को दोषी ठहराने के लिए राजी कर सकेंगे। उन मामलों में जहां व्यक्ति अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहते हैं, एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा समन जारी करने से पहले या सीजेएम द्वारा जांच का निर्देश देने के पहले जांच करने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद उत्पीड़न के तरीके के रूप में आपराधिक मानहानि का सहारा लेने पर अपनी नाराजगी जताई है।

मूल मुद्दा यह है कि क्या ऐसा कानून, जिसके फलस्वरूप संसद सदस्य की अयोग्यता साबित होती है, को वर्तमान सदस्य को सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए संशोधित करने की आवश्यकता है। चुनावी प्रक्रियाओं के दौरान उम्मीदवारों द्वारा किए गए भ्रष्ट आचरण के संदर्भ में भी, कानून उम्मीदवार को अपील दायर करने की अनुमति देता है लेकिन अपील का निर्णय आने से पहले अयोग्य नहीं ठहराता है। किसी सांसद या विधायक को यदि वह हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, जिसमें उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, या ऐसे अन्य अपराध जो गंभीर प्रकृति के हैं, जिनके लिए सात साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है, उसको सदस्यता से वंचित करने के बारे में समझा जा सकता है। वहां भी, कानून को दोषी उम्मीदवार को एक निश्चित अवधि के लिए दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अवसर देना चाहिए, जिसके दौरान सदन की उसकी सदस्यता अयोग्य न साबित हो।

2013 में एक अध्यादेश में 90 दिनों की अवधि प्रदान करने की मांग की गई थी, जिसके भीतर सजायाफ्ता सांसद या विधायक संसद या विधानसभा में अपनी सदस्यता की रक्षा के लिए दोषसिद्धि पर स्थगनादेश पा सकें। अध्यादेश कानून नहीं बन पाया और इसके परिणामस्वरूप, सांसदों या विधायकों को तुच्छ मामलों के आधार पर दोषी ठहराए जाने के लिए कोई सुरक्षा उपाय नहीं हैं।

सांसद दीपक बैज ने ईडी की कार्रवाई का मुद्दा लोकसभा में उठाया

पांच साल में की गई कार्रवाइयों का ब्यौरा सरकार से मांगा बैज ने, सरकार ने बताया कि पांच साल के भीतर दर्ज किए गए 3,497 मामले

जगदलपुर। क्षेत्रीय सांसद दीपक बैज अडानी मामले और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों के सांसदों के साथ विरोध प्रदर्शन में घंटों व्यस्त रहने के बावजूद लोकसभा में सवाल उठाने में पीछे नहीं रहे। श्री बैज ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई का मुद्दा पुरजोर तरीके से लोकसभा में उठाया। उन्होंने सरकार से बीते पांच सालों के दौरान ईडी द्वारा की गई कार्रवाइयों का ब्यौरा मांगा। श्री बैज के प्रश्न पर सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि पांच साल में ईडी ने कुल 3 हजार 497 मामले दर्ज किए हैं।

बस्तर के कांग्रेस सांसद दीपक बैज ने अतारांकित प्रश्न के जरिए केंद्रीय वित्तमंत्री से पूछा कि बीते पांच वित्तीय वर्षों के दौरान धन

शोधन और आर्थिक अपराधों के कुल कितने मामले दर्ज किए गए हैं और मामलों की राजयवार संख्या कितनी कितनी है? ईडी ने 25 मार्च 2023 तक पांच साल के दौरान ईडी द्वारा देश में शेल कंपनियों के विरुद्ध दर्ज मामलों की संख्या कितनी है और 20 मार्च 2023 तक विदेशी शेल कंपनियों के खिलाफ 5 साल में कितने मामले दर्ज किए गए हैं? श्री बैज के इन सवालों के जवाब में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने ब्यौरा प्रस्तुत किया। श्री चौधरी ने श्री बैज को जानकारी दी कि ईडी द्वारा धन शोधन के 2018 -19 में 195 मामले, 2019-20 में 562 मामले, 2020-21 में 981 मामले, 2021- 22 में 1180 मामले और 2022- 23 में 28 मार्च तक 579 मामलों समेत कुल 3 हजार 497 मामले दर्ज किए गए हैं। वित्त राज्यमंत्री ने बताया की ईडी की जांच में अनेक भारतीय और विदेशी शेल कंपनियों की भूमिका भी धन शोधन के मामलों में सामने आई है। इन मामलों में फेमा और पीएमएलए के प्रावधानों के मुताबिक कार्रवाई की गई है। वित्त राज्यमंत्री ने जनहित में और जांच में बाधा आने का हवाला देते हुए अन्य जानकारियों का खुलासा करने में असमर्थता जताई।

राहुल की लोकप्रियता से घबराकर भाजपा ने अलोकतांत्रिक कदम उठाया : उमेश देव

नगरी। जनपद सदस्य व सर्व आदिवासी तहसील नगरी के अध्यक्ष उमेश देव ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता निरस्त करने की निंदा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में लागू अघोषित आपातकाल की संज्ञा देते इसे लोकतंत्र का गला घोंटने वाली कार्यवाही करार दिया है। श्री उमेश देव ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की सदस्यता खारिज कर भाजपा ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के समय जनता का जैसा प्रतिसाद श्री गांधी को मिला है, उससे भयभीत होकर यह कदम उठाया गया है। भाजपा व आरएसएस की विखंडनकारी नीतियों को जनता के सामने श्री गांधी लगातार उजागर करते रहे हैं। उन्हें कन्याकुमारी से कश्मीर तक जनता ने जिस प्रकार से सराहा, उससे भाजपा घबरा गई है। इस घबराहट का परिणाम राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करना है। श्री गांधी की सदस्यता समाप्त करने को उमेश देव ने अडानी मामले से ध्यान भटकाने की भाजपाई चाल बताया है। उन्होने कहा है कि भाजपा विपक्षी एकता से घबरा गई है और अदाणी मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग से भाग रही है। भाजपा संरक्षित इस कारवाई का जवाब आगामी चुनावों में जनता देगी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मंहगाई, सामाजिक विद्वेष की भाजपा सरकार की नीतियों से जनता तंग आ चुकी है। इस बात को जानते व जनता के बीच राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर भाजपा ने यह अलोकतांत्रिक कदम उठाया है।

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस में आक्रोश

नगरी। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद से पूरे देश में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में नगरी बस स्टैंड में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर नारेबाजी की। विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। युवा कांग्रेस ने कहा अडानी के खिलाफ जो आवाज राहुल गांधी उठा रहे थे, उसको दबाने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया है, लेकिन हकीकत यह है कि मोदी सरकार लगातार अडानी को बचाने का प्रयास कर रही है. कांग्रेस कानूनी और राजनीतिक लड़ाई जारी रखेगी. यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि राहुल गांधी संसद में किसी भी तरह का कोई सवाल न कर सकें।भाजपा सरकार राहुल गांधी की आवाज को दबाने का काम कर रही है. यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष प्रमोद कुंजाम ने कहा राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता अलोकतांत्रिक तरीके से षड्यंत्र करके रद्द किया गया है। जो हमेसा देशहित मे आवाज़ बुलंद करते रहे।विपक्ष को पूरी तरह से खत्म करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, सरकार में बैठे हुए लोग पूरी तानाशाही चला रहे हैं. देश का युवा और यूथ कांग्रेस इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी सरकार की तानाशाही के खिलाफआज सड़कों पर है। आज हमने नगरी बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन एवं केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। बीजेपी सरकार की दमनकारी नीति के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ता लड़ाई लड़ता रहेगा। इस अवसर पर सिहावा विधायक डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, पूर्व विधायक अम्बिका मरकाम, विधायक प्रतिनिधि रुद्र प्रताप नाग, जिला पंचायत सदस्य द्रव मनोज साक्षी, मीना बंजारे, जनपद सदस्य उमेश देव, कैलाश प्रजापति, भानेन्द्र ठाकुर, आसिफखान, महेंद्र धेनुसेवक, निकेश ठाकुर,नदीम अली, सोनू चौहान,प्रेमांशु प्रजापति, प्रदीप सोन, तेजेन्द्र भट्ट, अभिषेक बंजारे, मुकेश लहरे, अंकुश देवांगन,अरविन्द यादव,गीतेश साव,विमला मरकाम,रेणुका शर्मा ,तबस्सुम खान,चैतन्य साहू,नरेश छेदहा,आदित्य ठाकुर, मनोज गुप्ता,बीरबल नागरची,रिंकू चिन्डा,सतीश साहू,नीलकमल साहू,रतेश्वर, भुसन भारती,विकाश ठाकुर,राजा खान,मनीष नेताम,नरहरि,सोहेल,रिखब पटेल,शिवेंद्र साहू,मनेंद्र साहू,गोलू देवांगन,आदि उपस्थित थे।

गलतफहमी में है प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस : अनिला भेड़िया

बालोद। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने राहुल गांधी को सजा एवं संसदीय सदस्यता खत्म किए जाने के मामले को लेकर बीजेपी और आरएसएस समेत प्रधानमंत्री पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी सोचते होंगे कि डरा धमकाकर राहुल गांधी को जेल भेजकर उनकी आवाज को दबाने प्रयास करेंगे तो वह गलत सोचते हैं।

राहुल गांधी काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनका अदम्य साहस देखने को मिला है और हम उनके समर्थन में लड़ाई जारी रखेंगे। अब तो दिल्ली कूच करने की भी तैयारी है। नरेंद्र मोदी की तानाशाही से देश के लोग उग्र हो रहे हैं।

मंत्री अनिला भेड़िया ने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने जो किया है वह गलत है। इसके बाद से कांग्रेस अब चुप बैठने वाली नहीं है। कांग्रेस के साथ-साथ अन्य विपक्षी दलों के लोग भी उग्र हो रहे हैं। पूरे देश की जनता में उनके प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है। मंत्री ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने जो देश को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली। लोगों का जुड़ाव हुआ उससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भयभीत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ मंत्री अनिला भेड़िया ने आरएसएस और बीजेपी को संयुक्त रूप से आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी को दबाने की कोशिश की तो कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। उनकी सेना सदैव लड़ाई के लिए तत्पर है। देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। यह जो कार्रवाई की जा रही है वह षडयंत्र पूर्वक कार्रवाई है। इसका हम सब कड़ा विरोध करते हैं। इसका परिणाम देखने को मिलेगा। राहुल गांधी ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं और ना ही उनकी सेना डरती और झुकती है।

धर्मांतरण पर हंगामा, दो परिवारों के खिलाफ ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट

■ बोले- कार्रवाई करें, नहीं तो हम करेंगे

बालोद। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब बालोद में ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं। गांव में दो परिवारों के धर्म परिवर्तन पर मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंच गए। उन्होंने दोनों परिवारों की नामजद शिकायत करते हुए कहा है कि प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई करे, नहीं तो ग्रामीणों को ही ठोस कदम उठाना होगा। ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों परिवारों ने अपना मूल धर्म छोड़ दिया है। गांव के रीति-रिवाजों को नहीं मानते हैं।

दरअसल, ग्राम सिवनी में मंगलवार को काम-धाम बंद कर दिया गया था। प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति का कलेक्ट्रेट

पहुंचना अनिवार्य किया गया था। ग्रामीणों ने बताया कि हम सब धर्मांतरण के खिलाफ हैं। गांव में जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर चुके हैं और कुछ लोग गुप्त रूप से ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। यह गांव के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। हिंदू हमारा मूल धर्म है और हम इसी के लिए जीते हैं किसी के लिए मरते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों परिवार ईसाई बन गए हैं और उसका गांव में प्रचार करते हैं।

शांति हो रही भंग

ग्रामीणों ने बताया कि गांव में दो परिवारों द्वारा शांति भंग की जा रही है। यह अपने धर्म का प्रचार लोगों के बीच करते हैं, जिससे आक्रोश पनपता जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि दोनों परिवार अन्य लोगों को भी अपने धर्म के बारे में बता कर धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके कारण गांव में अशांति हो रही है और कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि, हम धर्मांतरण के विरुद्ध लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं।

रीति रिवाज को मानते नहीं

धर्मांतरण की बड़ी बहस के बीच ग्रामीण अपने धर्म को बचाने निकले हुए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि हमारे ग्रामीण रीति रिवाज हैं, देवी-देवता है। कई सारी परंपराएं हैं, लेकिन यह दोनों दोपहर परिवार गांव के रीति रिवाज को तुच्छ नजर से देखते हैं। इसको नहीं मानते हैं। दोनों परिवार धर्म परिवर्तित हो गए हैं और स्पष्ट रूप से अपने इसाई धर्म का प्रचार करते देखे जाते हैं। अगर इन परिवारों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो यह हमारे गांव को ईसाई मिशनरी गांव के रूप में तब्दील कर सकते हैं।

नक्सलियों के आईईडी विस्फोट से बीएसएफ के 2 जवान घायल

■ दोनो घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर कर दिया गया

कांकेर। जिले के कोयलीबेड़ा ब्लॉक अंतर्गत चिलपरस के पास सर्चिंग पर निकले बीएसएफ के दो जवान सुशील कुमार और छोटूराम आईईडी की चपेट में आने से घायल हो गए हैं। घायल जवानों को उपचार के लिए कोयलीबेड़ा अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बीएसएफ के जवान मंगलवार की सुबह 08 बजे सर्चिंग में रवाना हुए थे, चिलपरस के पास नक्सलियों ने आईईडी लगा रखा था, जिसकी चपेट में आने से 02 जवान घायल हो गये।

कांकेर एसपी शलभ कुमार सिन्हा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि बीएसएफ के जवान सर्चिंग में

निकले हुए थे, इसी दौरान चिलपरस के पास बीएसएफ के 02 जवान इसकी चपेट में आ गए। घायल सुशील कुमार के चेहरे और आंख पर चोट लगी है वहीं छोटूराम के दाहिने पैर और हाथ में चोट आई है। घायल जवानों का प्राथमिक उपचार कोयलीबेड़ा स्वास्थ्य केंद्र में करने के बाद हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

दादर में अवैध निर्माण को हटाया अतिक्रमण दस्ते ने

कोरबा। नगर पालिक निगम कोरबा के अतिक्रमण दस्ते ने दादर में किए जा रहे अवैध कब्जे को जे.सी.बी. के माध्यम से तोड़कर हटा दिया। आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने आमनागरिकों से कहा है कि वे शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे का प्रयास न करें और ही बिना अनुमति प्राप्त किए किसी प्रकार का निर्माण कराएं, कोई भी निर्माण विधिवत अनुमति प्राप्त करने के बाद ही करें। नगर निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत दादर में अवैध रूप से बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराया जा रहा था, जिसको संज्ञान में लेते हुए आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने इस पर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही करने व अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। अतिक्रमण दस्ता प्रभारी योगेश राठौर ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन के सहयोग से जे.सी.बी. के माध्यम से किए जा रहे उक्त निर्माण को हटा दिया तथा अतिक्रमण से मुक्त कराया। आयुक्त शासकीय जमीन पर अतिक्रमण व अवैध कब्जे का प्रयास न करें, साथ ही कोई भी निर्माण कार्य करने के पूर्व निगम से विधिवत भवन निर्माण की अनुज्ञा प्राप्त करें।

नहर विवाद : पुलिस और किसानों के बीच हुई झूमाझटकी

रायगढ़। जिले के ग्राम नेतनागर में केलो परियोजना के नहर निर्माण का विरोध कर रहे 50 से अधिक किसानों को सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किसान पूरे साल पानी की मांग को लेकर पिछले 15 दिनों से नहर निर्माण के विरोध में धरने पर बैठे हुए थे। सप्ताह भर पहले किसानों ने पद यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। सोमवार की सुबह किसान फिर से धरने पर बैठे थे, इसी दौरान पुलिस बल मौके पर पहुंचा और विरोध कर रहे किसानों की गिरफ्तारी की। इस दौरान किसानों के साथ पुलिस की हल्की झूमा झटकी भी हुई। इधर किसानों का कहना था कि वे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। प्रशासन के समक्ष उन्होंने अपना पक्ष भी रखा था, लेकिन पुलिस उन्हें जबरिया गिरफ्तार कर रही है। उनके साथ बदसलूकी भी की गई है। गिरफ्तार किसानों ने इस दौरान नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। इधर पुलिस के साथ एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और पुलिस की मौजूदगी में नहर निर्माण का काम चालू कराया गया है।

निर्माण कार्यों को माह जून तक पूरा करने के निर्देश

कांकेर। कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला की अध्यक्षता एवं संसदीय सचिव श्री शिशुपाल शोरी की विशेष उपस्थिति में आज जिला कार्यालय में बैठक आयोजित कर निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई तथा निर्माण कार्यों को जून माह तक पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया। ऐसे कार्य जिनमें प्रशासकीय स्वीकृति सहित अन्य स्वीकृतियां प्राप्त की जानी है, उनमें त्वरित कार्यवाही करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये गये। बैठक में कांकेर शहर के सड़क चौड़ीकरण कार्य की भी समीक्षा की गई तथा उसमें प्रगति के संबंध में प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता को निर्देश दिये गये। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम विद्यालय भवनों की साफ-सफाई, शौचालय की व्यवस्था, रंगाई-पोताई इत्यादि की भी समीक्षा किया गया।

बरमकेला में 29 को फूड लाइसेंस शिविर

सारंगढ़/बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी के निर्देश पर उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ द्वारा जिले में फूड लाइसेंस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा एफएसएसएआई खाद्य अनुज्ञप्ति / पंजीयन शिविर ड्रीम कैफे़लेंधरा रोड़ बरमकेला में 29 मार्च को फूड शिविर का आयोजन किया गया है। पंजीयन का कार्य प्रातः 11 बजे से संध्याकालीन 4 बजे तक किया जाएगा। शिविर में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 के तहत रिपैकर ,रीलेबरर ,खाद्य परिवहन, थोक व खुदरा विक्रेता, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, किराना दुकान, मीट शॉप, पान ठेला, गुपचुप ठेला, गन्ना रस, खाद्य वर्फ विक्रेता व अन्य किसी भी प्रकार के खाद्य कारोबारकर्ता को लाइसेंस/पंजीयन प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार करने पर 6 माह का कारावास एवं एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कड़ी कार्यवाही की जा सकती है।

20 क्विंटल धान खरीदी के पर किसानों ने मनाया उत्सव

पाटन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किसानों को उनकी धान की उपज का उचित मूल्य दिलाने की दिशा में और कदम बढ़ाते हुए अब प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की है। 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी के फैसले को लेकर आज फेकारी धान खरीदी केंद्र में उत्साह मनाया गया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मना कर सरकार का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किसान नेता व डायरेक्टर अपेक्स बैंक छत्तीसगढ़ शासन राकेश ठाकुर थे, अध्यक्षता शाकम्भरी बोर्ड के सदस्य पवन पटेल ने किया। मुख्य अतिथि किसान नेता व डायरेक्टर अपेक्स बैंक छग शासन राकेश ठाकुर ने किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी के भूपेश सरकार के फैसले पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि किसान मुख्यमंत्री ही किसानो के दुख दर्द को समझ सकता है। किसानों को अब बढ़ी हुई मात्रा में धान बेचने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। समर्थन मूल्य में धान खरीदी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने राज्य के किसानों का हौसला बढ़ा है।

गेवरा खदान में कामगार नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल

■ प्रबंधन ने लगाया प्रतिबंध:

कोरबा। साउथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड एसईसीएल की गेवरा परियोजना में अब सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। महाप्रबंधक ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कार्य क्षेत्र में मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोयला व मिट्टी उत्खनन ओवहरबर्डन क्षेत्र वृहद संवेदनशील हैं। यहां कार्य के दौरान ध्यान भटकाव जोखिम भरा होता है।

एसईसीएल की गेवरा खदान में 2500 नियमित और इतने ही आउटसोर्सिंग के ठेका कर्मी कार्यरत हैं। कोयला उत्पादन के लिए सावेल, ड्रिल, डंपर, सरफेस माइनर कटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। अभी कर्मचारी मोबाइल लेकर कार्यस्थल में पहुंच रहे हैं। देखा यह जा रहा है कि आपरेटर वाहन चलाते समय एंड्राइड

मोबाइल का उपयोग करते हैं। इसकी वजह से उनका ध्यान भटकता है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। 15 दिन ही पहले ही खदान में पानी का छिड्डकाव करने वाली टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि वाहन चलाते वक्त आपरेटर मोबाइल का उपयोग कर रहा था। इसके पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। लागू किए गए सुरक्षा मानको को और सुदृढ़ करने गेवरा के महाप्रबंधक एसके मोहंती ने आदेश जारी कर खदान में कर्मचारियों को मोबाइल लेकर प्रवेश करने में प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रबंधन का मानना है कि इससे न केवल कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि खदान के कार्य अवधि में भी वृद्धि होगी। मोबाइल में कर्मचारी समय खराब नहीं करेंगे। इससे उत्पादन और कोयला परिवहन दोनों में वृद्धि होगी। आगे इस नियम को पूरे एसईसीएल के साथ कोल इंडिया से संबंद्ध अन्य कंपनियों में भी विस्तार किया जा सकता है। एसईसीएल के जनसंपर्क अधिकारी डा सनीष चंद्र ने बताया कि नियम के उल्लंघन पर आउटसोर्सिंग के ठेका कर्मियों को काम से पृथक कर दिया जाएगा। साथ ही हमेशा के लिए कोल इंडिया के आउटसोर्सिंग पर काम पर रखने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। नियमित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें निलंबन तक की सजा का प्राविधान निर्धारित किया गया है। साथ ही सेक्शन इंचार्ज भी जिम्मेदार होंगे।

खदान के अंदर कुछ स्थल ऐसे हैं, जहां कम रोशनी रहती है। इसकी वजह से भारी भरकम डंपर चलाने वाले आपरेटर को दूर से कर्मी नजर नहीं आते और दुर्घटनाएं हो जाती है। इससे भी निपटने सभी विभागीय व ठेका कर्मियों को लाल रंग का फ्लोरोसेंट जैकेट पहनना भी अनिवार्य कर दिया है। जैकेट में लगे रेडियम की वजह से दूर से ही कर्मचारी नजर आ जाएगा और दुर्घटना की आशंका कम हो जाएगी। 14 अप्रैल से यह नियम लागू होगा।

जेएसपीएल के सहयोग से स्टेडियम का जीर्णोद्धार

रायगढ़। स्टेडियम में खेल प्रशिक्षण हेतु निम्न आय वर्ग के भी बच्चे आते है, हमें उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए कि कम से कम फीस में उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करायें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को बेहतर सुविधाएं, वातावरण प्रदान कर उन्हे नई दिशा दें। जिससे वे खेलों में अपना भविष्य बनाने के साथ राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शहर का नाम रोशन करें। उक्त बातें कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने कलेक्टोरेट सभा कक्ष में आयोजित स्टेडियम समिति की बैठक में कही। इस अवसर पर निगम आयुक्त सौवित मिश्रा भी उपस्थित रहे। कलेक्टर सिन्हा ने रायगढ़ स्टेडियम समिति की बैठक में आय-व्यय, विद्युत देय, स्विमिंग पुल से 11 केव्ही लाईन विस्थापन, खेल युवा कल्याण विभाग का विद्युत मीटर पृथक, जेएसपीएल द्वारा जीर्णोद्धार एवं निर्माण, संग्रहित कबाड़ नीलामी, पार्किंग व्यावस्था, स्पोर्ट कोच नियुक्ति, स्पोर्ट काम्प्लेक्स में बढ़े हुए शुल्क निर्धारण, स्टेडियम में सॉफ्टवेयर के माध्यम से शुल्क एवं रसीद संग्रहण, सीसीटीवी कैमरा स्थापित, खेलो में उद्योगों की सहभागिता, स्टेडियम की ड्रेनेज समस्या जैसे विभिन्न बिंदुओं पर समिति के सदस्यों से विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। कलेक्टर सिन्हा ने आय व्यय की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि संभावित घटना के मद्देनजर स्विमिंग पुल से 11 के.व्ही लाईन विस्थापन करवा दी जाएगी। कलेक्टर सिन्हा ने शुल्क निर्धारण पर समिति की सदस्यों से चर्चा कि समिति के सदस्यों द्वारा कहा कि स्टेडियम में विभिन्न तबके के बच्चे होते ऐसे में पुराने तरह से फीस लिया जाए। जिसमें सभी संघ की सहमति बनी। कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि हमें कोशिश करना चाहिए कि कम से कम फीस रखे, जिससे सभी बच्चे खेल प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त कर सके। इस दौरान उन्होने स्टेडियम में होने वाले विद्युत व्यय पर कहा पृथक मीटर लगाया जाए एवं आयोजनकर्ता विद्युत भार का वाहन करें। कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि जेएसपीएल के माध्यम से स्टेडियम का जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है, जिसमें स्टेडियम को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जेएसपीएल एवं स्टेडियम समिति की बैठक किया जाए, जिसमें समिति अपना सुझाव प्रदान करें। जिससे कार्यो को और बेहतर तरीके से किया जा सके।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

स्मृति ने कांग्रेस के विरोध को लेकर राहुल पर निशाना साधा

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को उनके मोदी सरनेम वाले बयान पर आड़े हाथ लिया। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस के विरोध के बीच, स्मृति ईरानी ने गौतम अडानी के साथ रॉबर्ट वाड्रा की एक पुरानी तस्वीर को लेकर भी राहुल गांधी पर हमला किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को राहुल गांधी पर निशाना साधा क्योंकि अडानी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का विरोध जारी है। 2009 की एक तस्वीर का जिक्र करते हुए जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी के साथ दिखाया गया था, स्मृति ईरानी ने पूछा कि वाड्रा को अडानी के साथ हाथ मिलाते हुए क्यों देखा गया? केंद्रीय मंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूछा अगर उन्हें (राहुल गांधी को) अडानी से समस्या है, तो रॉबर्ट वाड्रा को अडानी के साथ हाथ मिलाते हुए क्यों देखा जाता है?

राहुल पर स्मृति के आरोपों पर कांग्रेस ने किया पलटवार

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के राहुल गांधी पर ताजे हमले को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने उनपर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ओबीसी के ठेकेदार ना बनें। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ओबीसी के नाम पर ये बस सियासत करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के ओबीसी को आसानी से गुमराह नहीं किया जा सकता। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी से भागते हुए प्रधानमंत्री मोदी आज स्मृति ईरानी को तैनात कर रहे हैं। स्मृति ईरानी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि क्या राहुल गांधी ने कहा कि वह घर खाली नहीं करेंगे? मैं 29 जून से सांसद हूं और मुझे 9 महिने से घर नहीं मिला और जिस व्यक्ति की सदस्यता चंद दिन पहले गई है उसे घर खाली करने का नोटिस आ गया। मंत्री महोदया (स्मृति इरानी) आपने कितने ही लोगों को 2-3 सालों के लिए घर दिए हुए हैं।

राहुल माफी मांगें, नहीं तो कराएंगे एफआईआर : रंजीत

नईदिल्ली। राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक ओर जहां मानहानि मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद उनके लोकसभा सदस्यता चली गई है। वहीं दूसरी ओर उनके बयान को लेकर सरगर्मियां जारी है। हाल में ही राहुल गांधी ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा था कि वह सावरकर नहीं हैं, राहुल गांधी है और गांधी कभी माफी नहीं मांगते। इसको लेकर अब सावरकर के पोते ने जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी पर पलटवार किया है। सावरकर के पोते ने पहले तो चुनौती दी थी राहुल गांधी इस बात को साबित करें कि सावरकर ने माफी मांगी थी। अब सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने साफ तौर पर कहा है कि अगर राहुल गांधी अपने बयान को लेकर माफी नहीं मांगते हैं तो मैं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराऊंगा। रंजीत सावरकर ने यह भी कहा कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे के मन में सावरकर के प्रति सम्मान हो सकता है, लेकिन जब तक वे सावरकर के लिए अपना समर्थन नहीं दिखाते, इसका कोई मतलब नहीं है।

उद्धव, आदित्य को मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने भेजा समन

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को मानहानि के मामले में समन जारी किया है। एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल रमेश शेवाले ने मानहानि मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें यह समन जारी किया गया है। कोर्ट ने शिवसेना नेता संजय राउत को भी समन भेजा है। कोर्ट अब इस मामले में 17 अप्रैल को सुनवाई करेगी। दरअसल शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के मुखपत्र सामना में बीते दिनों एक लेख लिखा गया था। इस लेख में शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता राहुल रमेश शेवाले का जिक्र किया गया था। इसी लेख को लेकर राहुल रमेश शेवाले ने उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ दीवानी मानहानि मामला दर्ज कराया था। शिवसेना का आरोप है कि इस लेख से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। बता दें कि सामना के जिस लेख को लेकर शेवाले ने केस दर्ज कराया है, उसकी हेडलाइन थी, राहुल शेवाले का कराची में होटल, रियल एस्टेट का कारोबार!

अन्नाद्रमुक के नए महासचिव बनें ई. पलानीस्वामी

चेन्नई। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के नए महासचिव के रूप में एडप्पादी पलानीस्वामी को नियुक्त किया गया है। इस दौरान अन्नाद्रमुक के मुख्यालय में जश्न मनाया गया। पलानीस्वामी पहले पार्टी के अंतरिम महासचिव थे। दरअसल, मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के कुमारेश बाबू द्वारा अन्नाद्रमुक महासचिव के चुनाव पर रोक लगाने की ओ पनीरसेल्वम और उनके समर्थकों की अंतरिम अर्जियों को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अन्नाद्रमुक के नए महासचिव की घोषणा करते हुए समर्थकों ने जश्न मनाया। न्यायामूर्ति के कुमारेश बाबू ने मंगलवार को ओ पन्नीरसेल्वम और उनके समर्थकों पीएच मनोज पांडियन, आर वैथिलिंगम और जेसीडी प्रभाकर द्वारा 11 जुलाई को अपनाए गए। एआईएडीएमके सामान्य परिषद के प्रस्तावों और महासचिव चुनावों के खिलाफ दायर अंतरिम आवेदनों को खारिज कर कर दिया है।

लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष का हंगामा

11वें दिन भी नहीं चल पाई संसद की कार्यवाही

नईदिल्ली। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। लेकिन दूसरे चरण में संसद में जबरदस्त हंगामा अब तक देखने को मिला है। यह हंगामा आज 11 वें दिन भी जारी रहा। हंगामे की वजह से 11वें दिन भी दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं हो सकी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों को 29 मार्च 11: 00 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर भाजपा लगातार उनसे माफी की मांग कर रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग को लेकर अड़ा हुआ है। इन्हीं दोनों मांगों पर सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। हंगामे और नारेबाजी की वजह से सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा इस तरह चला कि पीठासीन की ओर कागज फेंके गए जिसे भाजपा ने शर्मनाक आचरण बताया।

लोकसभा की कार्यवाही

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिये जाने के विरोध स्वरूप काले कपड़े पहनकर आए कांग्रेस के सदस्यों ने मंगलवार को निचले सदन में भारी हंगामा किया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजकर करीब सात मिनट पर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गयी। कांग्रेस के कुछ सांसदों ने प्रश्नकाल में कागज फाड़कर आसन की ओर फेंके और एक सदस्य ने आसन के सामने काला कपड़ा रखने का भी प्रयास किया। राम्या हरिदास, ज्योतिमणि सहित कांग्रेस के कुछ सदस्यों को आसन की ओर कागज फाड़कर फेंकते देखा गया जबकि टी एन प्रतापन ने आसन के सामने मेज पर काला कपड़ा रखने का प्रयास किया।

राज्यसभी की कार्यवाही

अडाणी समूह से जुड़े मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित किए जाने की मांग करते हुए विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा में मंगलवार को भी हंगामा किया जिससे उच्च सदन में लगातार 11वें दिन भी गतिरोध जारी रहा और एक बार के स्थगन के बाद बैठक को दोपहर दो बजकर तीन मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। कुछ सदस्यों ने काले कपड़े पहने हुए थे। कांग्रेस के कुछ सदस्य आसन के समक्ष भी आ गए तथा ''मोदी अडाणी भाई भाई'' के नारे लगाए।

खिलाड़ियों को दी गई बधाई

महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों की शानदार उपलब्धि की सराहना करते हुए राज्यसभा में मंगलवार को उन्हें बधाई दी गई। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा ''एक अच्छी खबर है। महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने सराहनीय प्रदर्शन किया और चार स्वर्ण सहित पांच पदक जीते हैं।'' उन्होंने कहा कि निकहत ज़रीन, लवलीना बोरगोहेन, नीतू गंघास और स्वीटी बूरा ने अपनी उपलब्धियों से देश को गौरवान्वित किया है।

मजबूत लड़ाई के लिए रहे तैयार : प्रधानमंत्री

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने पार्टी के नेताओं से मजबूत लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी ने सांसदों को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि छह अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हम 6 अप्रैल से 14 अप्रैल (बीआर अंबेडकर के जन्मदिन) सप्ताह को सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर 15 मई से 15 जून तक सभी सांसदों को अपने-अपने क्षेत्र देखने को कहा है। सांसदों को अपने क्षेत्र में किसी भी माध्यम से प्रचार करने को कहा गया है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि भाजपा संसदीय दल की बैठक में समाज कल्याण योजना पर चर्चा हुई। मन की बात अप्रैल में अपना 100वां एपिसोड पूरा करेगी, इसलिए पीएम मोदी ने सभी सांसदों से कहा है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र की खास बातें बताएं। पूर्वोत्तर में हाल के चुनावों में जीत के लिए हमने पीएम मोदी को भी बधाई दी। इसी दौरान प्रह्लाद जोशी से कर्नाटक में मुस्लिम कोटा खत्म करने पर सवाल पूछा गया। प्रह्लाद जोशी ने कहा कि यह तथ्यात्मक, कानूनी और संवैधानिक रूप से गलत है। जब अन्य राज्यों में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था और अब यह भी अवैध था इसलिए इसे खत्म कर दिया गया है। मंगलवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक में शामिल होने वाले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताओं को यह कहते हुए मजबूत लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा कि पार्टी जितनी अधिक उठेगी और सफल होगी, विपक्ष के हमले उतने ही अधिक होंगे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक मंगलवार सुबह यहां संसद परिसर में हुई। यह पहली बार था जब सत्र के चल रहे दूसरे भाग में यह बैठक हुई है। पीएम मोदी की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब संसद में गतिरोध बना हुआ है जिसमें विपक्ष अडानी-हिंडनबर्ग मुद्दे पर जेपीसी की मांग कर रहा है, और भाजपा ने राहुल गांधी से प्रधानमंत्री का अपमान करने के लिए माफी की मांग की है।

राहुल को बंगला खाली करने के नोटिस पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष

राहुल अपनी माँ या फिर मेरे साथ रह सकते हैं : खड़गे

नईदिल्ली। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनका आधिकारिक बंगला खाली करने के लिए कहे जाने को लेकर सरकार पर पलटवार किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वे उन्हें (राहुल गांधी को) कमजोर करने की हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वह बंगला खाली करते हैं तो वह अपनी मां के यहां जाकर रह सकते हैं या अगर हमारे पास आएंगे तो हम अपने घर में जगह देंगे। मैं एक बंगला खाली कर दूंगा।

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह मानहानि के एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए गए राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक उन्हें आवंटित सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है। लोकसभा की आवासीय समिति ने यह फैसला लिया जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता को 12 तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगला खाली करने का पत्र भेजा। राहुल 2005 से इस बंगले में रह रहे हैं।

खड़गे ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार के रवैए को अनुचित ठहराया और इसकी निंदा की। उन्होंने कहा, मैं उन्हें डराने, धमकाने और अपमानित करने के लिए सरकार के रवैये की निंदा करता हूं। यह तरीका नहीं है। कभी-कभी, हम तीन-चार महीने तक बिना बंगले के रहते हैं। मुझे अपना बंगला छह महीने बाद मिला। लोग ऐसा दूसरों को अपमानित करने के लिए करते हैं।

उधर राज्य सभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ''राहुल को बंगला खाली करने के लिए कहा गया है। ....उनका जमीर मर चुका है। तुच्छ लोगों की तुच्छ राजनीति।''

बंगला खाली करने के नोटिस पर राहुल गांधी ने लिखा भावुक खत

नईदिल्ली। संसद सदस्यता से अयोग्य ठहराने के बाद बंगला खाली करने के लिए दी गयी नोटिस का जवाब राहुल गांधी ने दे दिया है। राहुल गांधी ने लोकसभा सचिवालय को लिखे पत्र में कहा, पत्र के लिए धन्यवाद, मैं इसका पालन करूंगा।

राहुल गांधी ने लोकसभा सचिवालय को लिखे पत्र में कहा, पिछले चार कार्यकाल से लोकसभा सदस्य होने के नाते, यह जनता का जनादेश है, जिसके प्रति मैं यहां बिताये समय की सुखद स्मृतियों का ऋणी हूं। उन्होंने आगे लिखा, पूर्वाग्रह के बिना, मैं, निश्चित रूप से आपके पत्र में निहित विवरण का पालन करूंगा। राहुल 2005 से इस बंगले में रह रहे हैं। गौरतलब है कि मानहानि के एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए गए राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक उन्हें आवंटित सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है। लोकसभा की आवासीय समिति ने यह फैसला लिया जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता को 12 तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगला खाली करने का पत्र भेजा।

खेल
प्रमुख समाचार

आईपीएल 2023 : पंजाब से बेयरस्टो तो दिल्ली से पंत बाहर

नई दिल्ली। आईपीएल 2023 की शुरुआत 31 मार्च से हो रही है। सभी टीमें इस टूर्नामेंट की तैयारी में जुट गई हैं। हालांकि, कई टीमों को टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही बड़ा झटका लगा है। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। वहीं, मुंबई इंडियंस के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी चोट की वजह से इस सीजन नहीं खेलेंगे। पंजाब किंग्स के लिए जॉनी बेयरस्टो इस सीजन नहीं दिखेंगे। वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स के श्रेयस अय्यर चोट के चलते शुरुआती मुकाबलों से बाहर हो चुके हैं। उनकी जगह नीतीश राणा को टीम की कमान सौंपी गई है।

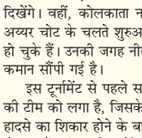

इस टूर्नामेंट से पहले सबसे बड़ा झटका दिल्ली की टीम को लगा है, जिसके कप्तान ऋषभ पंत कार हादसे का शिकार होने के बाद पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। पंत कई सर्जरी करा चुके हैं और वह इस साल के अंत तक क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर सकते हैं। दिल्ली ने पंत की जगह डेविड वॉर्नर को अपना नया कप्तान बनाया है। हालांकि, पंत की जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं किया है।

दिल्ली के अलावा मुंबई को भी बड़ा झटका लगा है। मुंबई के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पीठ की चोट के चलते इस सीजन में नहीं खेलेंगे। बुमराह ने अपनी पीठ की सर्जरी कराई है और उनका वनडे विश्व कप में खेलना भी मुश्किल है। मैदान में लौटने के बाद उनके लिए फिटनेस हासिल करना बड़ी चुनौती होगी। कोलकाता की टीम भी मुश्किल में फंसी हुई है, क्योंकि श्रेयस अय्यर पीठ की चोट से जूझ रहे हैं। खबरों के अनुसार एनसीए ने उन्हें सर्जरी कराने की सलाह दी है, लेकिन वह फिलहाल आईपीएल टीम के साथ हैं और सर्जरी को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। हालांकि, वह शुरुआती मैचों से बाहर हो चुके हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 40 अंक टूटा निफ्टी 17000 के नीचे

नई दिल्ली। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी मंगलवार को शुरुआती बढ़त गंवा कर लाल निशान पर बंद हुए। जहां वित्तीय सेक्टर शेयरों में मजबूती से शुरुआती कारोबार में बढ़त दिखी वहीं आईटी शेयरों में गिरावट के कारण बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 40.14 (0.07%) अंकों की गिरावट के साथ 16,951.70 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर, निफ्टी 34.00 (-0.20%) अंकों की गिरावट के साथ 16,951.70 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। रुपया डॉलर के मुकाबले 11 पैसे की मजबूती के साथ 82.20 रुपये के भाव पर बंद हुआ। आज के कारोबार में हैवीवेट शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है।

पीएफ में अब जमा रकम पर मिलेगा अधिक ब्याज

नईदिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मंगलवार को अपनी बैठक में 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.15 फीसदी की ब्याज दर निर्धारित कर दी। ईपीएफओ 2021-22 के लिए अपने करीब पांच करोड़ अंशधारकों के ईपीएफ पर ब्याज दर को घटाकर मार्च, 2022 में चार दशक से भी अधिक समय के निचले स्तर 8.1 फीसदी पर ले आया था। यह दर 1977-78 के बाद से सबसे कम थी, तब ईपीएफ पर ब्याज दर आठ फीसदी हुआ करती थी। 2020-21 में यह दर 8.5 फीसदी थी। एक सूत्र ने कहा, 'कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने मंगलवार को अपनी बैठक में 2022-23 के लिए ईपीएफ पर 8.15 फीसदी की दर से ब्याज देने का निर्णय लिया है।' मार्च, 2021 में सीबीटी ने 2020-21 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को 8.5 फीसदी कर दिया था।

सेबी ने डीमैट अकाउंट के लिए नॉमिनेशन की डेडलाइन बढ़ाई

नईदिल्ली। नए वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले ही बाजार नियामक सेबी की तरफ से निवेशकों के लिए राहत की खबर है। सेबी ने डीमैट अकाउंट नॉमिनेशन की समयसीमा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। सेबी की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक, डीमैट खातों का नॉमिनेशन अब 30 सितंबर 2023 तक कराया जा सकेगा। पहले यह समयसीमा 31 मार्च 2023 थी। बाजार नियामक सेबी ने कहा कि यह निर्णय हितधारकों से प्राप्त रिप्रजेंटेशन और उन ट्रेडिंग और डीमैट खातों के आकलन के आधार पर लिया गया है जिनमें नॉमिनेशन को अपडेट नहीं किया गया है। इसके साथ ही सेबी ने कहा कि जिन खातों में नॉमिनेशन पर कोई अपडेट नहीं है, उन्हें 30 सितंबर के बाद ट्रेडिंग और डेबिट के लिए बंद कर दिया जाएगा। निवेशकों के पास नॉमिनेशन से बाहर निकलने का विकल्प भी है।

शेयर बाजारों की निगरानी प्रणाली में अदाणी की ग्रीन एनर्जी कंपनी

नईदिल्ली। शेयर बाजार एनएसई और बीएसई ने कहा कि अदाणी ग्रीन एनर्जी को मंगलवार, 28 मार्च से दीर्घकालिक अतिरिक्त निगरानी कदम (ASM) के दूसरे चरण के दायरे में रखा जाएगा। शेयर बाजारों के परिपत्रों में यह जानकारी दी गई। इसमें कहा गया कि अदाणी ग्रीन एनर्जी ASM रूपरेखा के दायरे में बनी रहेगी लेकिन 28 मार्च से इसे संबंधित उच्च चरण में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इससे पहले एनएसई और बीएसई ने अदाणी समूह की दो कंपनियों अदाणी टोटल गैस और अदाणी ट्रांसमिशन को दीर्घकालिक ASM के दूसरे चरण से हटाकर शुक्रवार को पहले चरण में रख दिया था। इससे पहले, 17 मार्च को दोनों शेयर बाजारों ने अदाणी ग्रीन एनर्जी और एनडीटीवी को दीर्घकालिक ASM के पहले चरण में रखा था।

सरकार के प्रयासों से घरेलू स्टार्टअप पर नहीं पड़ा असर

नईदिल्ली। अमेरिका-यूरोप में बैंकिंग संकट का दुनियाभर के वित्तीय बाजारों व बड़ी कंपनियों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। लेकिन, भारत में इस संकट का खास असर नहीं दिखा है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक (एसवीबी) के दिवालिया होने के बाद सरकार ने घरेलू स्टार्टअप की मदद के लिए तत्काल कदम उठाए। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि स्टार्टअप पर इस संकट का प्रतिकूल असर न पड़े।

वैष्णव ने सोमवार को भारत वैश्विक मंच कार्यक्रम में कहा, सिलिकॉन वैली बैंक के पतन के बाद हमने (सरकार) तुरंत कदम उठाया और पूरे स्टार्टअप समुदाय के साथ जुड़े। यह भी सुनिश्चित किया कि सिलिकॉन वैली बैंक में जमा घरेलू स्टार्टअप का पैसा भारतीय बैंकों में आसानी से स्थानांतरित हो सके। विभिन्न सरकारी इकाइयों के बीच सहयोग से प्रक्रिया को सुचारू रूप से अंजाम दिया गया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, स्टार्टअप समुदाय भारतीय बैंकों को अपना भरोसेमंद साथी मानें। कहीं भी किसी भी बैंक में पैसा लगाने के बारे में न सोचें। अपना पैसा भारत में रखें। सिलिकॉन वैली बैंक में जमा रकम भारतीय बैंकों में स्थानांतरित करने के लिए तत्काल उठाए गए कदम

बनेंगे सेमीकंडक्टर का प्रमुख विनिर्माण केंद्र

वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भारत जैसा भरोसेमंद भागीदार महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में माना जा रहा है कि भारत को प्रमुख सेमीकंडक्टर विनिर्माण गंतव्य के रूप में उभरना चाहिए। सरकार देश में जीवंत सेमीकंडक्टर विनिर्माण परिवेश तंत्र बनाने के लिए पूरी ईमानदारी व लगन से काम कर रही है। - अश्विनी वैष्णव, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

देश में क्रांटम कंप्यूटिंग आधारित पहला दूरसंचार नेटवर्क लिंक शुरू

दूरसंचार मंत्री ने कहा, क्रांटम कंप्यूटिंग आधारित देश का पहला दूरसंचार नेटवर्क लिंक दिल्ली में शुरू हो चुका है। पहले 'अंतरराष्ट्रीय क्रांटम एनक्रेल' में उन्होंने कहा, राष्ट्रीय राजधानी में संचार भवन व सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के बीच क्रांटम कम्युनिकेशन लिंक शुरू हो चुका है।

फर्स्ट सिटीजन बैंक को एसवीबी के अधिग्रहण की मंजूरी

फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने फर्स्ट सिटीजन बैंक एंड ट्रस्ट कंपनी को सिलिकॉन वैली बैंक (एसवीबी) के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। बिक्री में एसवीबी के सारे जमा और कर्ज की बिक्री भी शामिल है।

प्रौद्योगिकी में भारत का साथ चाहती है दुनिया

वैष्णव ने कृत्रिम मेधा (एआई) और क्रांटम कंप्यूटिंग क्षेत्रों में भारत के तेजी से उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, एक समय था जब भारत को केवल प्रौद्योगिकी उपभोक्ता माना जाता था। आज कई वैश्विक कंपनियां भारतीय स्टार्टअप, उद्यमियों और शिक्षाविदों को अपने भागीदार के रूप में पसंद करती हैं। इसका प्रौद्योगिकी के विकास पर सकारात्मक असर पड़ा है।

सऊदी नेशनल बैंक के चेयरमैन का इस्तीफा

क्रेडिट सुइस के बारे में टिप्पणी करने वाले सऊदी नेशनल बैंक के चेयरमैन अम्मार अल-खुदेयरी ने निजी कारणों का हवाला देकर पद से इस्तीफा दे दिया। खुदेयरी ने 15 मार्च को कहा था कि क्रेडिट सुइस का सबसे बड़ा शेयरधारक सऊदी नेशनल बैंक संकटग्रस्त बैंक को और पूंजी नहीं देगा। इसके बाद क्रेडिट सुइस के शेयर 30त्न से अधिक टूट गए थे।

क्या अब अदालतों में तय होगा राजनीतिक भविष्य?

अनिल तिवारी

संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव व्यवस्थाओं का वर्णन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और अन्य ब्रिटिश कानूनों में चुनाव का जिम्मा कार्यपालिका पर होने से केवल मजाक होता था। संविधान सभा में भी स्वतंत्र चुनाव आयोग की राय उभरी थी। चुने हुए व्यक्तियों में कदाचार की भी संभावना व्यक्त की गई थी। इसीलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 (1) तथा (2) में ऐसे अपराध वर्णित हैं जिनमें कम या ज्यादा सजा होने पर भी तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता से अयोग्यता लागू हो जाती है। स्वर्गीय राजीव गांधी के काल में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (4) के अनुसार 2 वर्ष या अधिक के लिए दोष सिद्ध हो कर सजा प्राप्त सांसदों और विधायकों को तब तक के लिए कुर्सी पर बने रहने का अभयदान दे दिया गया जब तक उनके आपराधिक प्रकरणों से संबंधित अपीलों का आखिरी निपटारा नहीं हो जाता। 1989 में आए इस संशोधित प्रावधान के 16 साल बाद लोक प्रहरी नामक संस्था की ओर से लिली थॉमस ने जनहित याचिका के रूप में इसे चुनौती दी। 10 जुलाई 2013 को न्यायमूर्ति एके पटनायक और एसजे मुखोपाध्याय की बेंच ने उपरोक्त धारा 8 (4) को असंवैधानिक करार दिया। सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय को बताया गया कि दोष सिद्ध सांसद या विधायक को कोई लाभ नहीं मिलता है उनका मकसद केवल सदन की संरचना की सुरक्षा है। सरकार की ओर से खड़े वकीलों का यह भी तर्क था कि अपराधिक अपीलीय न्यायालय केवल सजा को स्थगित कर सकते हैं दोष सिद्धि के तर्क को नहीं। इसके विरोध में तर्क दिया गया कि नवजोत सिंह सिद्धू बनाम पंजाब राज्य 2007, रमा नारंग बनाम रमेश नारायण 1955, रवि कांत एस पाटिल बनाम स्वभाव एस बंगाली 2007 जैसे प्रकरणों में उच्चतम न्यायालय ने साफ साफ कहा है कि मुनासिब प्रकरणों में दोष सिद्धि के प्रभाव को भी अपीलीय न्यायालय तथा हाई कोर्ट द्वारा अपील के निराकरण तक स्थगित किया जा सकता है। कई प्रकरणों में ऐसे आदेश पारित भी हुए हैं। तब अदालत का कहना था कि दोष सिद्धि को भी स्थगित कराने का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना होगा। सामान्य तौर पर मजिस्ट्रेट के दंड आदेश या देश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 में अपील की जाती है। अपील पेश करने के बाद धारा 389 के अंतर्गत अपील लंबित रहने तक दंड आदेश या अन्य आदेश का निलंबन और अपीलार्थी को जमानत पर छोड़े जाने के आवेदन किए जा सकते हैं। रमन के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अपीलीय न्यायालय को धारा 389 के तहत दंड आदेश को स्थगित करने का जो अधिकार है उससे दोष सिद्धि को स्थगित करने का अधिकार भी मिल जाता है। हालांकि धारा 482 के तहत अतिरिक्त रिवीजन न्यायालय और हाई कोर्ट को भी पूरा अधिकार है कि वह दोष सिद्धि के दंड को स्थगित कर दें।

लिली थॉमस के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने सबको सामान्य नागरिक की कोठी में लाकर खड़ा कर दिया था। मनमोहन सिंह की सरकार ने अदालत के इसी फैसले को निष्क्रिय करने के लिए अध्यादेश पारित कराया था जिसकी प्रतियां राहुल गांधी ने फाड़ते हुए कहा था क्या बकवास है। राहुल गांधी के प्रकरण में एक वाक्य के कारण 2 वर्ष की सजा दे दी जो भारत के इतिहास में शायद अनोखी है। इस मामले में अदालत की अति सक्रियता भी काबिले गौर है। छोटी अदालतों से निकलने वाले फैसले किस तरह लिए जाते हैं इससे कमोबेश हर आदमी परिचित है। रसूखदार लोग अपने पक्ष में अक्सर फैसला करवाते रहते हैं। ऐसे हालात में लोक प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन आवश्यक है। नहीं तो अंग्रेजों के जमाने में बने कानूनों का सहारा लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे को निशाना बनाते रहेंगे।

सावरकर का अपमान क्यों करते हैं राहुल

विष्णु शर्मा

वीर सावरकर पर राहुल गांधी द्वारा लगाये गये माफीनामे के आरोप के जवाब में केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 6 ट्वीट की एक लम्बी थ्रेड अपने ट्विटर एकाउंट से शेयर की। इस थ्रेड में सावरकर की तारीफ में इंदिरा गांधी का तो वो पत्र था ही, कुछ और नई बातों का उन्होंने दावा किया। ये बातें आम लोगों के लिए चौंकाने वाली थीं। अनुराग ठाकुर ने एक नया दावा किया कि, सावरकर जी ने यह इज्जत ऐसे ही नहीं कमाई। उस दौर के जितने भी बड़े नेता थे, सावरकर जी की देशभक्ति और साहस के आगे नतमस्तक थे। यहां तक कि कांग्रेस ने भी 1923 के काकीनाडा अधिवेशन में सावरकर जी के लिए रिजोल्यूशन पास किया था। ऐसे में सभी को ये जानने की उत्सुकता होगी कि आखिर कांग्रेस ने इस अधिवेशन में सावरकर के लिए, क्या रिजोल्यूशन पास किया था।

काकीनाडा आंध्रप्रदेश में हैं और 1923 में यहां कांग्रेस का अधिवेशन तब हुआ था, जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के बाद से जेल में थे। इसी अधिवेशन के बाद उन्हें अगले अधिवेशन से पहले छोड़ दिया गया था और तब 1924 में वह पहली और आखिरी बार कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। उनके सम्मान में कांग्रेस अधिवेशन स्थल का नाम गांधीपुरम रखा गया था। अधिवेशन के लिए इस 120 एकड़ जमीन को स्थानीय राजा ने दिया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष खिलाफत आंदोलन वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। मौलाना मोहम्मद अली भी जेल में थे। बाहर आए तो गांधीजी की सलाह पर मोहम्मद अली जौहर को 1923 के काकीनाडा अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया था। वह कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले छठे मुस्लिम थे। काकीनाडा अधिवेशन में हिंदू-मुस्लिम एकता पर अच्छे भाषण के बावजूद इस्लाम को लेकर उनकी कट्टरता बहुत से कांग्रेसियों को रास नहीं आ रही थी। यहां तक कि काकीनाडा अधिवेशन में भी खिलाफत के पंडाल के अलावा एक मस्जिद भी अधिवेशन स्थल गांधी नगर की मूल योजना में शामिल की गई थी, जबकि कोई मंदिर, चर्च या गुरुद्वारा नहीं था। ऐसे में तमाम सावरकर प्रशंसक कांग्रेसियों ने दबाव बनाया कि काला पानी की कड़ी सजा काट रहे विनायक सावरकर और उनके भाई की रिहाई के लिए कांग्रेस प्रस्ताव पारित करे। तब जाकर सावरकर परिवार के लिए ये तीन लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया, इसमें लिखा था, "This Congress condemns the continued incarceration of Vinayak Damodar Sawarkar (Swatantryaveer) and expresses its sympathy with Dr N. D. Savarkar and other members of his family".

इस प्रस्ताव में सबसे ज्यादा गौर करने लायक है कि सावरकर को अब माफी वीर कहने वाली कांग्रेस ने तब के रिजोल्यूशन में उन्हें स्वातंत्र्यवीर भी बोला था। इतना ही नहीं, यह शब्द रिजोल्यूशन पास करने के बाद अध्यक्ष मोहम्मद अली ने भी दोहराया था और बताया कि कैसे विनायक सावरकर के भाई गणेश सावरकर उनके साथ बीजापुर जेल में बंद थे, जो अब छोड़ दिए गए हैं। अनुराग ठाकुर ने अपनी ट्वीट थ्रेड की शुरुआत भगत सिंह से की है और लिखा है कि, राहुल उन स्वातन्त्र्य वीर सावरकर का अपमान करते हैं, जिनकी किताब भारत का प्रथम स्वातंत्र्य समर का पंजाबी में अनुवाद करवाकर बांटने के लिए खुद भगत सिंह जी वीर सावरकर जी से मिलने रत्नागिरी गए थे, और छापी भी। इस ट्वीट के साथ उन्होंने प्रभात प्रकाशन से छपी भगत सिंह जेल नोट बुक का वो पेज भी शेयर किया है, जिसमें सावरकर की किताब से भगत सिंह के लिखे गए नोट्स हैं। आज सावरकर विरोधी भगत सिंह की जयंती पर दोनों को अलग अलग ध्रुव पर खड़ा करते हैं जबकि हकीकत में इन दोनों शख्सियतों का आपस में कभी कोई विवाद रहा ही नहीं। बल्कि उलटे भगत सिंह ने वीर सावरकर की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर लिखी किताब 1857 का स्वातंत्र्य समर का तीसरा एडीशन छपवाया और संगठन के लिए धन इकट्ठा करने के लिए उसकी कीमत भी ज्यादा रखी। इसके लिए उन्होंने बाकायदा रत्नागिरी जाकर सावरकर से मुलाकात की और उनसे उनकी पुस्तक को छापने की अनुमति ली। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य ये है कि सावरकर की लिखी यही पुस्तक भगत सिंह की बायोग्राफी में उन पुस्तकों में शामिल है जिनसे उन्होंने प्रेरणा ली थी। लेकिन आपको हर कोर्स की किताब या भगत सिंह से जुड़ी फिल्मों में बताया जाएगा कि फांसी वाले दिन भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे।

सवाल है कि भगत सिंह लेनिनवाद से ही इतने प्रभावित थे तो बाकी किताबें भगत सिंह की आधिकारिक सूची में क्या कर रही थीं? अगर भगत सिंह ने अन्य किताबें पढ़ीं थीं, तो उनके बारे में क्यों नहीं बताया जाता? भगत सिंह ने अलग अलग भाषाओं की जो देसी या विदेशी पुस्तकें पढ़ी थीं, उनकी सूची आप लुधियाना की शहीद भगत सिंह रिसर्च कमेटी के वेब पेज पर भी पढ़ सकते हैं और तस्दीक कर सकते हैं कि भगत सिंह खाली लेनिन की ही किताब नहीं पढ़ रहे थे बल्कि तिलक की गीता रहस्य, राजा महेन्द्र प्रताप की जीवनी, सचिन्द्रनाथ सान्याल की बंदी जीवन के साथ वीर सावरकर की 1857 का स्वातंत्र्य समर भी पढ़ रहे थे। वीर सावरकर की एक और किताब थी, जिससे कई उद्धरण भगत सिंह ने अपनी जेल नोटबुक में लिए हैं। उस किताब का नाम था हिंदू पदपादशाही। अब जो उद्धरण इस किताब से भगत सिंह ने लिए हैं, उनको पढ़िए- 1) बलिदान तभी पूज्नीय है, जब सफलता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, लेकिन तार्किक रूप से इसकी अनिवार्यता सिद्ध होती हो। जो बलिदान अंत में सफलता की ओर अग्रसर नहीं करता, वो आत्महत्या है और मराठा युद्धनीति में इसकी कोई जगह नहीं थी। 2) धर्मान्तरित होने की बजाय मार डाले जाओ... (उस समय हिंदुओं के बीच यही पुकार प्रचलित थी) लेकिन रामदास उठ खड़े हुए और कहा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, धर्मान्तरित होने से बेहतर है कि मार डाले जाओ, काफी है लेकिन इससे भी अच्छा ये प्रयास करना है कि न तो मारे ही जाओ और न ही धर्मान्तरित हो बल्कि स्वयं हिंसक शक्तियों को मार डालो। यदि मृत्यु अनिवार्य हो.. मारे जाओ, लेकिन जीत हासिल करने के लिए मारते हुए मरो, धर्म के लिए जीत हासिल करो। 3) हमारे युग की सबसे निराशाजनक बात ये है कि हमें बिना इतिहास बनाए इसे लिखना पड़ रहा है। बिना साहसिक क्षमता और अवसरों के उन वीरतापूर्ण गीतों को गाना पड़ रहा है, जिन्हें हम जीवन में कभी वास्तविक नहीं बना सके। इन्हीं नोट्स को अनुराग ठाकुर ने अपनी ट्वीट थ्रेड में शेयर किया है। उसके साथ ही उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री का लिंक भी शेयर किया है, जो इंदिरा गांधी के आदेश पर बनवाई गई थी। उसमें सावरकर की महानता के पुल बांधे गए हैं। लेकिन फिर भी यह तय है कि राहुल अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे और सावरकर को लेकर तमाम अपमानजनक बयान भविष्य में भी देते रहेंगे क्योंकि उन पर कम्युनिस्टों की काली छाया पड़ चुकी है। लेकिन यह भी तय है कि नए तथ्य सामने आने से जनता की नजरों में राहुल के ये बयान फीके साबित होंगे और उनकी भद्द पिटेगी।

प्रसंग

जाको राखे साइयों

महाराष्ट्र सन्त का कुम्हार ने नित्य के समान पहले दिन तैयार किये घड़ों को आ पर रखा, किन्तु एक बड़े में रात्रि को उनकी पालतू बिल्ली ने बच्चे जने थे और इस बात से रोका अनभिज्ञ थे। दोपहर को जब बिल्ली वहाँ आयी, तो वह आवे के चारों ओर घूम- घूमकर चिल्लाने लगी। राँका जान गये कि किसी घड़े में इसके बच्चे होंगे और इस कारण यह विलाप कर रही है। उन्हें बड़ा ही पश्चात्ताप हुआ और स्वयं पर हत्या का पाप लगेगा, यह सोचकर जोर जोर से रोने लगे। वे दुःख के मारे लोटने लगे और भगवान् का स्मरण कर बोले, हे विट्ठल ! जब तक इन बच्चों को जीवन दान नहीं दोगे, तब तक मुझे चैन नहीं आयेगा। जब तुम लाक्षागृह में पाण्डवों की रक्षा कर सकते हो, गजेन्द्र को मगर के चंगुल से मुक्त कर सकते हो, प्रह्लाद को अग्नि से बचा सकते हो, तो निश्चय ही इन अबोध बच्चों की भी रक्षा कर सकते हो। मुझे यह जानकर दुःख हो रहा है कि तुमने मुझे क्यों पता न चलने दिया कि घड़े में बच्चे भी थे। उनकी पत्नी को जब बात मालूम हुई, तो वह भी उनके साथ क्रन्दन करने लगी। तीन दिन तक वे दोनों इस प्रकार विलाप करते रहे और भगवान् का स्मरण करते रहे। आबाँ बुझने पर जब उन्होंने घड़ा बाहर निकाला, तो उन्हें यह देख आश्चर्य हुआ कि जिस घड़े में वे बच्चे थे, उसे तनिक भी आँच नहीं पहुँची थी। अन्य कुम्हारों ने भी जान लिया कि यह भगवान् की कृपा का फल है। रॉका की पत्नी ने पति को बताया कि भगवान् ने उसकी मनौती स्वीकार की है और इसी कारण बच्चे जीवित रहे। मनौती के बारे में राँका द्वारा पूछे जाने पर वह बोली कि उसने मनौती की थी कि यदि बच्चे जीवित निकलेंगे, तो वह अपनी सारी चीजें ब्राह्मणों को लुटा देगी। तब तो तुम्हारी मनौती का ही यह फल हैं- यह कहकर राँका ने अपनी सारी चीजों को ब्राह्मणों को देकर भिक्षा द्वारा जीवन बसर करना शुरू किया।

आज की महत्वपूर्ण घटनाएं

2001 संयुक्त राज्य अमेरिका ने ग्लोबल वार्मिंग पर किए गए क्योटो संधि को मानने से इंकार कर दिया।
2004 आयरलैंड कार्यस्थलों पर ध्रूम्रपान प्रतिबंधित करने वाला पहला देश बना।
2008 दुनिया के 370 शहरों ने पहली बार ऊर्जा बचत करने के लिए अर्थ आवर मनाने की शुरूआत की।
2010 इस्लामवादी चेचन अलगाववादियों ने मॉस्कोमेट्रो पर दो बम गिराए, जिसमें कम से कम 40 मारे गए और 100 से अधिक लोग घायल हो गए।
2011 फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सेंट लुइस के अध्यक्ष जेम्स बुलार्ड ने फेडरल रिजर्व से अमेरिकी ट्रेजरी की खरीद को सीमित करने का आह्वान किया क्योंकि यह मुद्रास्फीति की आग को फ़ीड करता है।
2013 ट्यूरिन के कफन पर नए शोध का समर्थन करता है कि यह वास्तव में यीशु मसीह के कपड़े के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अनुसंधान ने 300 ईसा पूर्व और 400 ईस्वी के बीच कफन की तारीख के लिए यांत्रिक और थर्मल माप का उपयोग किया।
2013 स्टैनफोर्ड की सालगिरह पर अमेरिकी बायोइन्जिनेर्स ने एक ट्रांजिस्टर बनाया जैसे ट्रांसक्रिप्टर डीएनए और आरएनए अणुओं से बना है।
2014 एंड्रेज किस्का स्लोवाकिया के राष्ट्रपति चुने गए।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

योगतत्त्वापनिषद् (भाग-01)

यह उपनिषद् कृष्ण यजुर्वेद से सम्बद्ध है। इसमें योग विषयक विविध उपादानों का विस्तृत वर्णन किया गया है। भगवान् विष्णु के द्वारा पितामह ब्रह्मा के लिए योग विषयक गूढ़ तत्त्वों के निरूपण के साथ उपनिषद् का शुभारम्भ हुआ है। कैवल्य रूपी परमपद की प्राप्ति के लिए योग मार्ग ही श्रेष्ठ साधन बताया गया है। मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग एवं राजयोग के क्रम में इनकी चार अवस्थाओं (आरम्भ, घट, परिचय एवं निष्पत्ति) का वर्णन हुआ है। आगे चलकर योगी के आहार-विहार एवं दिनचर्या का उल्लेख किया गया है। उसी क्रम में योगसिद्धि के प्रारम्भिक लक्षणों का वर्णन तथा उससे सावधान रहने का निर्देश भी दिया गया है। पूर्णमनोयोग से की गयी योगसाधना निःसन्देह सफल होती है, जो योगी साधक को सभी सिद्धियों (अणिमा, गरिमा, महिमा आदि) से सम्पन्न कर देती है, वह ईश्वरीय शक्तियों का अधिकारी बन जाता है। अन्ततः वह आत्मतत्त्व का निर्वात दीपशिखा की तरह अन्तःकरण में साक्षात्कार करके आवागमन से मुक्त हो जाता है। इसी फलश्रुति के साथ योगतत्त्व उपनिषद् का समापन हुआ है। विष्णु नामक महायोगी ही समस्त (भूत) प्राणियों के आदि महाभूत एवं महातपस्वी हैं।

पितामह ब्रह्माजी ने उन जगत् के स्वामी (भगवान् विष्णु) की आराधना एवं प्रणाम करके, कहा- हे जगन्नाथ! आप अष्टाङ्ग युक्त योग का उपदेश मुझे प्रदान करें।

कैवल्य रूपी परम पद, अन्य दूसरे मार्गों का आश्रय लेने से कठिनता से प्राप्त होता है। भिन्न-भिन्न शास्त्रों के मतों में पड़कर ज्ञानी जनों की बुद्धि मोह-ग्रस्त हो जाती है।

(यहाँ यह प्रश्न उठता है कि) जब वह परमात्मा सभी भाव और पद से परे, नित्य, ज्ञानरूप एवं मायारहित है, तब वह जीव भाव को कैसे प्राप्त हो जाता है। उस विशुद्ध परमात्मा ने सुख-दुःख से युक्त होकर जीव-भावना की, इससे उसे जीव नाम दिया गया। भय, दुःख, विषाद, हर्ष आदि समस्त दोषों से मुक्ति मिल जाने पर जीव को केवल (विशुद्ध) माना गया है। अब उन दोषों को दूर करने का उपाय कहता हूँ। योग-विहीन ज्ञान मोक्ष देने वाला कैसे हो सकता है ? ज्ञानरहित योग से भी मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। इस कारण मोक्ष के अभिलाषी को ज्ञान और योग दोनों का ही दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। क्रमशः...

आध्यात्मिक आंदोलन के प्रणेता थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस

रमेश सर्राफ धमोरा

स्वामी रामकृष्ण परमहंस भारत के एक ऐसे महान संत एवं विचारक थे जिन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया था। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति की। अपनी साधना से रामकृष्ण इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं है। वे ईश्वर तक पहुंचने के भिन्न-भिन्न साधन मात्र हैं। रामकृष्ण परमहंस अपने समय के महान साधक व मानवता के पुजारी थे।

रामकृष्ण परमहंस का जीवन और व्यक्तित्व रहस्यमयी रहा। उनकी जीवन-शैली और उनका व्यवहार अच्छे-अच्छों की भी समझ से बाहर का था। इतना अजीब था कि ज्यादातर लोग उन्हें पागल तक समझते थे। कुछ ने तो उनके दिमाग का इलाज कराने तक की कोशिश की। लेकिन ढाका के एक मानसिक चिकित्सक ने उनकी युवावस्था में ही एक बार कहा था कि असल में यह आदमी एक महान योगी और तपस्वी है। जिसे दुनिया अभी समझ नहीं पा रही है। और किसी चिकित्सकीय ज्ञान से उसका इलाज नहीं किया जा सकता है।

रामकृष्ण परमहंस के पास जो कोई भी जाता वह उनकी सरलता, निश्छलता, भोलेपन और त्याग से इतना अभिभूत हो जाता कि अपना सारा पांडित्य भूलकर उनके पैरों पर गिर पड़ता था। गहन से गहन दार्शनिक सवालों के जवाब भी वे अपनी सरल भाषा में इस तरह दे देते कि सुनने वाला तत्काल ही उनका मुरीद हो जाता। इसलिए, दुनियाभर की तमाम आधुनिक विद्या, विज्ञान और दर्शनशास्त्र पढ़े महान लोग भी जब दक्षिणेश्वर के इस निरक्षर परमहंस के पास आते, तो अपनी सारी विद्वता भूलकर उसे अपना गुरु मान लेते थे।

रामकृष्ण परमहंस महान योगी, उच्चकोटि के साधक व विचारक थे। सेवा पथ को ईश्वरीय, प्रशस्त मानकर अनेकता में एकता का दर्शन करते थे। सेवा से समाज की सुरक्षा चाहते थे। रामकृष्ण का सारा जीवन अध्यात्म-साधना के प्रयोगों में बीता। वे लगातार कई घंटों तक समाधि में लीन हो जाते थे। चैबीस घंटे में बीस-बीस घंटों तक वे उनसे मिलनेवाले लोगों का दुख-दर्द सुनते और उसका समाधान भी बताते। रामकृष्ण परमहंस के भोले प्रयोगवाद में वेदांत, इस्लाम और ईसाइयत सब एकरूप हो गए थे। निरक्षर और पागल तक कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन से दिखाया था कि धर्म किसी मंदिर, गिरजा, विचारधारा, ग्रंथ या पंथ का बंधक नहीं है।

रामकृष्ण परमहंस मुख्यतः आध्यात्मिक आंदोलन के प्रणेता थे। जिन्होंने देश में राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाया। उनकी शिक्षा जातिवाद एवं धार्मिक पक्षपात को नकारती हैं। रामकृष्ण ने इस्लाम, बोद्ध, ईसाई, सिख धर्मो की बकायदा विधिवतरुप से शिक्षा ग्रहण कर साधनायें की थी। ब्रह्म समाज के सर्वश्रेष्ठ नेता केशवचंद्र सेन, पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर, वंकिमचंद्र चटर्जी, माइकेल मधुसूदन दत्त, कृष्णदास पाल, अश्विनी कुमार दत्त से रामकृष्ण घनिष्ठ रुप से परिचित थे।

बेमानी होतीं वैश्विक संस्थाएं

डॉ अश्विनी महाजन

हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-20 समूह के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज दुनिया में बहुपक्षवाद संकट में है। लगभग यही बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दोहराई है। गौरतलब है कि जब से भारत ने जी-20 की अध्यक्षता संभाली है, दुनिया में वैश्विक संस्थाओं समेत कई मुद्दों पर चर्चा जोर पकड़ रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पहले द्वि-ध्रुवीय विश्व और बाद में अमरीका की अगुआई वाले एक-ध्रुवीय विश्व में भी वैश्विक संस्थानों की महती भूमिका मानी जाती रही है। संयुक्त राष्ट्र और उसके अंतर्गत आने वाली संस्थाएं दुनिया के संचालन की धुरी बनी रहीं।

कहीं द्वंद्व या संघर्ष हो या प्राकृतिक या मानव जनित आपदा हो, तमाम मुल्क संयुक्त राष्ट्र की ओर ही देखते रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ही नहीं, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आदि की विशेष भूमिका रही है। वर्ष 1995 से पहले 'गैट' और उसके बाद विश्व व्यापार संगठन वैश्विक व्यापार को संचालित करने वाले नियमों के निर्धारक के रूप में जाने जाते रहे हैं।

लेकिन आज इन संस्थाओं और उनकी कार्य पद्धति तथा वैश्विक नेतृत्व की उनकी क्षमता पर ही नहीं, उनकी नीयत पर भी सवाल उठ रहे हैं। महामारी, वैश्विक संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, दुनिया में बढ़ती खाद्य असुरक्षा और कई मुल्कों पर बढ़ते असहनीय कर्ज के कारण इन संस्थाओं के माध्यम से वैश्विक शासन पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। यही स्थिति संप्रभुता संकट, असंतुलन, संघर्ष और द्वंद्व, स्वतंत्र राष्ट्रों के अस्तित्व के लिए खतरा बन रही है। जैसे समाधान इन संस्थानों से अपेक्षित है, वे उसमें असफल दिख रहे हैं। महामारी के शुरू से लेकर उसके निवारण के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन केवल नकारा ही साबित नहीं हुआ, बल्कि उसके प्रमुख द्वारा चीन की तरफदारी करने के कारण बदनाम भी हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठन भी सम्मेलन और बैठक करने वाले संगठन बन कर रह गये हैं। विभिन्न मुल्कों का भी अब उन पर कोई विशेष विश्वास नहीं रह गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन महामारी के समय इसके प्रारंभ के बारे में भी निष्पक्ष राय नहीं दे सका। टीकाकरण के मामले में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ कमाने के लालच पर भी वह अंकुश नहीं लगा पाया।

जब यह अपेक्षा थी कि महामारी के दौरान आवश्यक दवाओं, टीकों और उपकरणों पर पेटेंट स्थगित किये जायेंगे तथा सभी प्रकार के इलाज और टीके रॉयल्टी मुक्त उपलब्ध होंगे, पर व्यापार संगठन की 'व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार' (ट्रिप्स) काउंसिल में पहले तो कोई निर्णय ही नहीं हो पाया और बाद में भी केवल टीकों के संबंध में ही शर्तों के साथ हुए निर्णय ने संगठन की असंवेदनशीलता तथा बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विकसित देशों की मानवता के प्रति उदासीनता को उजागर कर दिया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष जलवायु सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में एक लक्ष्य रखा गया है कि 2050 तक दुनिया का औसत तापमान इस शताब्दी के प्रारंभ के औसत तापमान से दो डिग्री सेल्सियस से ज्यादा न बढ़े। जापान के क्योटो में हुए जलवायु सम्मेलन में यह सहमति बनी थी कि 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के अधिक उत्सर्जन करने वाले देशों को उत्सर्जन को घटाना पड़ेगा, कुछ अन्य को अपने उत्सर्जन को समान रखने और शेष को अपने विकास के मद्देनजर उत्सर्जन को बढ़ाने की भी अनुमति थी। इस सहमति को 'क्योटो प्रोटोकोल' के नाम से जाना जाता है। इस संधि का तो पालन हुआ, लेकिन क्योटो के बाद भी कई सम्मेलन हुए और सम्मेलनों की यह प्रक्रिया जारी है। इस शृंखला में एक सम्मेलन नवंबर, 2022 में ही संपन्न हुआ है। कुछ वर्ष पूर्व इस सम्मेलन में एक सहमति बनी थी कि दुनिया के धनी देश विकासशील देशों को 100 अरब डॉलर हर वर्ष उपलब्ध करायेंगे, ताकि वे उत्सर्जन घटाने के लिए अपने देशों में क्षमता निर्माण कर सकें।

लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि जहां वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने के लिए प्रौद्योगिकी और निवेश की भारी जरूरत है, लेकिन इस हेतु विकसित देश अपने दायित्व का निर्वहन करने में अभी तक असफल रहे हैं। विकसित देश अपनी तकनीक भी देने के लिए तैयार नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र, उसके सम्मेलन और संस्थान इस संबंध में अप्रभावी दिखते हैं। विश्व में एक समय अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाने वाली इन वैश्विक संस्थाओं पर लंबे समय से प्रश्नचिह्न लगते रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब लगभग 75 साल से अधिक पुरानी वैश्विक संस्थाओं का आकर्षण ही नहीं, बल्कि प्रभाव भी धूमिल होने लगा है, बदले हुए हालात में नयी वैश्विक शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा के लिए माहौल बनने लगा है। आज जब भारत जी-20 देशों की अध्यक्षता का निर्वहन कर रहा है, विश्व के समक्ष चुनौतियों के समाधान के लिए नयी सोच और नयी व्यवस्था की जरूरत को वैश्विक मंचों पर रेखांकित करना समय की जरूरत है। वर्तमान वैश्विक संस्थाओं के संविधानों में चाहे विश्व बंधुत्व, शांति, विकास, परस्पर सहयोग जैसी बातों का जिक्र है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बड़े देश ही उन सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे।

गांधी आज

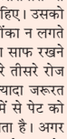

इलाज (भाग-02)

गतांक से आगे...

सेक की जरूरत हो जैसे फोड़े को पकाना हो, साँस लेने में कष्ट कठिनाई होती हो, थकावट या सर्दी की पीड़ा हो तो गरम पानी में छोटा तौलिया निचोड़कर खाल जल न जाय इस प्रकार सेंक लेने से बहुत आराम मिलता है। बालू मिट्टी या ईंट से भी उसे गरम करके कपड़े में लपेटकर, जले नहीं इसका ध्यान रखते हुए सेंक लिया जा सकता है। किसी के बीमार होते ही तुरंत उसका बिछौना दूसरे लोगों से अलग कर देना चाहिए। उसके आसपास से आदमियों और चीज वस्तु की भीड़ कम कर देनी चाहिए। उसको इस तरह लिटाना चाहिए जिससे काफी प्रकाश और झोंका न लगते हुए हवा मिल सके। उसके कपडे, चादर ओढ़ना वगैरा साफ रखने चाहिए। उसके कंबल, बिछौने, तकिया वगैरा को दूसरे तीसरे रोज तेज धूप में रखना चाहिए। बीमार को दबा देने से ज्यादा जरूरत है उसके शरीर, मन और पेट को आराम देने की। इनमें से पेट को आराम देने की बात पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। अगर भुखमरी से ही रोग न लगा हो तो रोगी को चाहे जो मर्ज हुआ हो, उसका पेट बिगड़ा न हो ऐसा क्वचित ही होता है। इसलिए, उसके पेट को हलका करना उपचारक का पहला काम है। इसके लिए इस विषय में गांधीजी की आरोग्य-साधन पुस्तक पढ़नी चाहिए। वरित (एनिमा) देना पहला उपाय है, और अगर बुखार जर का न हो तो एकाध जुलाब दिया जा सकता है। इसके साथ एक या दो लंघन कराने में तो कोई हानि है ही नहीं। यदि बीमार बहुत कमजोर हो तो उसे अधिक उपवास कराए जायें या नहीं, इसके लिए किसी अनुभवी की सलाह लेना आवश्यक है।

क्रमशः...

देश का भविष्य युवाओं के सपनों से गढ़ा जाएगा

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल

बिलासपुर। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय परिसर में राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री विश्वभूषण हरिचंदन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर फिजी गणराज्य के भारत में उच्चायुक्त श्री कमलेश शशि प्रकाश मौजूद थे। समारोह में विश्वविद्यालय के 58 और शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ के 7 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक एवं डिग्री से अंलकृत किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा समाज विज्ञान और कला संकाय में योगदान के लिए 2 विद्वानों को मानद् उपाधि से विभूषित किया गया। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने गणित एवं अंग्रेजी विषय के 2 शोधकर्ता विद्यार्थी को पहली बार पीएचडी की उपाधि प्रदान की। कार्यक्रम में संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि आशीष सिंह, बेलतरा विधायक श्री रजनीश सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री ए.डी.एन वाजपेयी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ के कुलपति डॉ. ललित प्रकाश पटेरिया, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय

दुर्ग की कुलपति डॉ. अरूणा पल्टा विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर राज्यपाल श्री हरिचंदन ने अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका कन्हार का विमोचन किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री हरिचंदन ने स्वर्ण पदक एवं मानद उपाधि प्राप्त सभी विद्यार्थी एवं विद्वानों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के सपनों और आशाओं से गढ़ा जाएगा। दीक्षांत समारोह विद्यार्थी और यूनिवर्सिटी के लिए एक यादगार दिन होता है। आपने विश्वविद्यालय में जो शिक्षा अर्जित की है, वो एक बेहतर और प्रगतिशील समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। विद्यार्थियों को सतत अपनी क्षमता और ज्ञान के विकास के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा सरकार ने शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा को शामिल किया गया है, जिसमें बच्चों के संपूर्ण विकास पर जोर दिया जा रहा है। आज हम अपनी प्राचीन समृद्ध ज्ञान और परम्परा को भूल गए है। अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को फिर से अर्जित करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में मानवीय मूल्यों और परम्पराओं को शामिल करना होगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय मूल्यों, परम्पराओं और रचनात्मक क्षमता का विकास होता है। विद्यार्थी नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते है। मुख्य अतिथि उच्चायुक्त श्री कमलेश शशि प्रकाश ने विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि पढ़े-पढ़े और खूब पढ़े इसे अपनी आदत में शामिल कर ले। पढ़ाई से ही आपके सपनों को उंची उड़ान मिलेगी। उन्होंने कहा कि अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें और उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करें। कुलपति श्री ए.डी.एन वाजपेयी ने स्वागत भाषण दिया और विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की जानकारी दी और कुल सचिव श्री शैलेन्द्र दुबे ने आभार व्यक्त किया।

मानद् उपाधि से इन्हें नवाजा गया

फिजी गणराज्य के भारत में उच्चायुक्त श्री कमलेश शशि प्रकाश को समाज विज्ञान संकाय ने मानद् उपाधि और सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉ0 पुष्पा दीक्षित को कला संकाय में डी. लिट की उपाधि दी गई। विश्वविद्यालय में शोधकर्ता दो विद्यार्थियों को गणित एवं अंग्रेजी विषयों में पहली बार पीएचडी की उपाधि दी गई।

हेलीपेड पर राज्यपाल का प्रथम न्यायधानी आगमन पर स्वागत -

राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन के प्रथम न्यायधानी आगमन पर प्रशासन द्वारा पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय हेलीपेड पर उनका स्वागत किया गया। श्री हरिचंदन अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए शहर पहुंचे। हेलीपेड पर संभागायुक्त डॉ0 संजय अलंग, बिलासपुर आईजी श्री बी.एन.मीणा, कलेक्टर श्री सौरभ कुमार एवं पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया।

श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की नई दरें निर्धारित

रायपुर। श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिको के लिए एक अप्रैल 2023 से 30 सितम्बर 2023 तक के लिए न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की गई है। यह दरें 45 अनुसूचित, सामान्य नियोजन के लिए प्रतिदिन 20 रूपए और प्रतिमाह 260 रूपए की वृद्धि की गई है। कृषि नियोजन में कार्य श्रमिको के लिए 225 रूपए प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। इसी तरह से अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए प्रति एक हजार अगरबत्ती के लिए 5 रूपए 85 पैसे की वृद्धि की गइ है। न्यूनतम वेतन की निर्धारित दरों के लागू होने पर अब अकुशल श्रमिक जोन 'अ' के लिए 10 हजार 480 रूपए, जोन 'ब' के लिए 10 हजार 200 रूपए और जोन 'स' के लिए 9 हजार 960 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है। इसी तरह से अर्द्धकुशल श्रमिको को जोन 'अ' के लिए 11 हजार 130 रूपए, जोन 'ब' के लिए 10 हजार 870 और 'स' के लिए 10 हजार 610 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम देय होगा। इसी तरह से कुशल श्रमिको जोन 'अ' के लिए 11 हजार 910 रूपए, 'ब' के लिए 11 हजार 650 रूपए और जोन 'स' के लिए 11 हजार 390 न्यूनतम वेतन देय होगा। उच्च कुशल श्रमिको को जोन 'अ' के लिए 12 हजार 990 रूपए, 'ब' के लिए 12 हजार 430 रूपए और जोन 'स' के लिए 12 हजार 170 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन मिलेगा। कृषि श्रमिको के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन अकुशल कृषि श्रमिको के लिए 8 हजार 400 रूपए प्रतिमाह दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगरबत्ती निर्माण श्रमिकों के लिए अगरबत्ती रोलर्स में एक हजार अगरबत्ती बनाने पर 32 रूपए 81 पैसे और सुगींधत सेंटेड अगरबत्ती बनाने पर 33 रूपए 51 पैसे देय होगा। श्रमायुक्त ने बताया है कि एक अप्रैल से प्रभावशील यह न्यूनतम वेतन दरें श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाईट https://cglabour.nic.in/ पद पर भी उपलब्ध है। साथ ही श्रमायुक्त कार्यालय इंद्रावती भवन खण्ड तीन, द्वितीय तल नवा रायपुर से भी सम्पर्क कर जानकारी ली जा सकती है।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रदेशवासियों को दुर्गाष्टमी और महानवमी की दी बधाई

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को दुर्गाष्टमी और महानवमी की बधाई और शुभकामनाएं दी है। श्री बघेल ने नवरात्रि के पावन अवसर पर मां दुर्गा से प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शक्ति उपासना के पर्व नवरात्रि के अवसर पर पूरे देश में नौ दिनों तक देवी के नौ रूपों की भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जाती है। इनमें अष्टमी और महानवमी विशेष महत्व रखते हैं। इस अवसर पर घरों, मंदिरों में कन्या भोज कराया जाता है। शक्ति स्वरूपा देवी हमारे घरों में कन्याओं के रूप में आती हैं। श्री बघेल ने कहा है कि हर बेटी देवी स्वरूपा है, इसलिए नवरात्रि के नौ दिन ही नहीं बल्कि हमेशा बेटियों और महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा का भाव बनाए रखें। इससे हम सच्चे अर्थों में देवी उपासना को सार्थक कर सकते हैं।

आवास दिलाने के नाम पर ठगी महिला आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। राजधानी में सरकारी आवास योजना में आवास दिलाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी हो गई। आरोपी सोनाली दत्ता ने 30-35 लोगों से सरकारी आवास दिलाने के नाम पर 6 लाख रूपए ठग लिए। पुलिस ने दोपहर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गोपाल नगर गुढियारी निवासी ललीत मानिकपुरी में थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 14 सितंबर2020 से 22 के बीच मोबाईल 9981397795 धारक सोनल दत्ता ने फोन कर खुद को मंत्रालय में परिचित का होना बताया, कहा कि 90 दिनों में इंद्रा आवास योजना में तहत मकान मिल रहा है। जिसके लिए कार्यालय के अधिकारियों को कुछ पैसे देने होंगे। इस एवज में सोनल दत्ता ने ललित मानिकपुरी से 20 हजार की मांग की। जिसपर उसके झांसे में आकर उसने मांगी गई रकम उसके खाते में भेज दिया। जिसके बाद दो साल बीत जाने के बाद भी न मकान मिला और न ही दिए गए पैसा वापस किया गया। आरोपी से मकान के बारे में पूछताछ करने पर कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद दोबारा उसे फोन करने पर उसका नम्बर बंद आने लगा। जानकारों से पूछताछ करने पर पता चला की आरोपी ने अन्य 30-35 लोगों से भी इंद्रा आवास का मकान दिलाने का झांसा देकर ठगी कर मोटी रकम वसूले। इस पर ठगी होने के शक में ललित ने थाना में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई।

श्री जैतूसाव मठ में रामनवमीं पर्व धूम-धाम से मनाया जायेगा

रायपुर। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी पारंपरिक रुप से श्री जैतूसाव मठ में रामनवमीं पर्व धूम-धाम से मनाया जायेगा। श्री ठाकुर रामचंद्र जी स्वामी जैतूसाव मठ सार्वजनिक न्यास की ओर से भक्तजनों से आग्रह किया गया है कि सभी पूजा व प्रसाद ग्रहण कर पहुंचे। श्री अजय तिवारी ने बताया कि 30 मार्च गुरुवार दोपहर 12 बजे भगवान श्रीराम जी की जन्म आरती, 31 मार्च शुक्रवार दोपहर 1 बजे से राजभोग आरती ,4 अप्रैल मंगलवार दोपहर 12 बजे से श्रीराम जी की छट्ठी आरती पश्चात् प्रसाद वितरण किया जायेगा।

रेलवे स्टेशन में मोबाइल चोर गिरफ्तार

रायपुर। रेलवे स्टेशन टिकट काउंटर के पास यात्रियों के जेब से मोबाइल, पर्स चुराने वाले शख्स को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से चोरी का मोबाईल जब्त किया गया। रायपुर रेलवे पुलिस अधीक्षक जेआर ठाकुर एवं उप रेल पुलिस अधीक्षक एस एन अख्तर के दिशा निर्देश में रेसुब मंडल टास्क टीम एंव जीआरपी संयुक्त टीम के द्वारा स्टेशन पर यात्रियों का सामानों की चोरी करने वाले आरोपियों की धरपकड़ जारी है। स्टेशन में लगे सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखी जा रही है।

पोषण पखवाड़ा: मिलेट्स को दैनिक जीवन में अपनाएं युवा

रायपुर। पोषण पखवाड़े के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आज यूनिसेफ के सहयोग से युवाओं में पोषण जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय वेबीनार का आयोजन किया गया। वेबीनार के माध्यम से युवाओं को मिलेट्स के फायदे समझाते हुए उन्हें दैनिक जीवन में मिलेट्स को शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया। वेबीनार से फेसबुक लाइव के माध्यम से नेहरू युवा केन्द्र, भारत स्काउट-गाइड्स, एनएसएस, यूनिसेफ सहित विभागीय अमले सहित बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया।

महिला एवं बाल विकास विभाग के नोडल अधिकारी श्री जी.एस.मरावी ने बताया कि 20 मार्च से महिला एवं बाल विकास द्वारा अन्य विभागों के सहयोग से पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान लोगों में पोषण जाकरूकता और व्यवहार परिवर्तन के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। विभागीय अधिकारी श्रीमती रश्रुति नेरकर ने कहा कि पहले पूर्वज श्री अन्न या मिलेट्स का प्रयोग करत थे। लेकिन बदलते समय में घरों में खानपान की शैली बहुत बदल गई है। मिलेट्स को फिर भोजन में शामिल कर पोषण के सभी फायदे लिये जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग कुपोषण से लंबे समय से लड़ाई कर रहा है। बच्चों, महिलाओं, किशोरियों को पोषण आहार और रेडी टू ईट प्रदान किया जा रहा है। लेकिन इसमें विभाग के साथ समाज के हर व्यक्ति की सहभागिता जरूरी है। पोषण संबंधित व्यवहार और खानपान परिवर्तन में युवा बड़ी भूमिका निभा सकते है। मिलेट्स से कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं। युवा जंक फूड को छोड़कर पौष्टिक भोजन और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें।

यूनिसेफ के न्यूट्रीशन विशेषज्ञ श्री महेन्द्र प्रजापति ने बताया कि मिलेट्स पचने में आसान होते हैं इसलिए बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक के लिए उपयोगी हैं। इसमें सारे पौष्टिक तत्व मिल जाते हैं। कम पानी और जमीन में अधिक उपज के कारण यह पर्यावरण के भी अनुकूल है। ये ज्यादा महंगे भी नहीं होते। उन्होंने बताया कि किशोरावस्था में वृद्धि और विकास तेजी से होता है। इस समय संतुलित आहार लेना जरूरी है। आजकल प्रोसेस्ड फूड के दुष्प्रभाव के कारण कुपोषण और मोटापा अधिक देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि 2016 से 18 के बीच किये गए न्यूट्रीशन सर्वे के अनुसार बड़ी संख्या में किशोर और किशोरियों में आयरन, विटामिन ए, डी और विटामिन बी-12 की कमी देखी गई। यह भी पाया गया है कि बड़ी संख्या में किशोर नमक, शक्कर और फैट रिच फूड लेते हैं। प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड में कैलोरी बहुत ज्यादा होती है और प्रोटीन और फाइबर बहुत कम होते हैं।

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने कल 0-16 वर्ष के बच्चों को कराया जाएगा स्वर्ण प्राशन

रायपुर। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने 29 मार्च को रायपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया जाएगा। आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में हर पुष्य नक्षत्र तिथि में शून्य से 16 वर्ष के बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया जाता है। चिकित्सालय के कौमारभृत्य बाल रोग विभाग में सवेरे नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक इसका सेवन कराया जाता है। यह औषधि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, श्वसन संबंधी एवं अन्य रोगों से रक्षा करने के साथ ही एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ाने में अत्यंत लाभकारी है। यह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में भी मदद करता है।

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. लवकेश चंद्रवंशी ने बताया कि आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष की आगामी पुष्य नक्षत्र तिथियों 29 मार्च, 27 अप्रैल, 24 मई, 20 जून, 18 जुलाई, 14 अगस्त, 10 सितम्बर, 7 अक्टूबर, 4 नवम्बर, 1 दिसम्बर और 29 दिसम्बर को बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया जाएगा।

चंद्रवंशी ने बताया कि आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. डॉ. जी.एस. बघेल, चिकित्सालय अधीक्षक प्रो. डॉ. प्रवीण कुमार जोशी और बाल रोग विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. नीरज अग्रवाल के निर्देशन में हर पुष्य नक्षत्र तिथि में महाविद्यालय चिकित्सालय में बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष की आगामी पुष्य नक्षत्र तिथियों 29 मार्च, 27 अप्रैल, 24 मई, 20 जून, 18 जुलाई, 14 अगस्त, 10 सितम्बर, 7 अक्टूबर, 4 नवम्बर, 1 दिसम्बर और 29 दिसम्बर को बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया जाएगा।

नवसृजन मंच ने किया 101 बेटियों के माता-पिता का सम्मान

रायपुर। प्रदेश की प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था नवसृजन मंच द्वारा बहुआयामी आयोजन बिटिया जन्मोत्सव के अंतर्गत 101 बेटियों के माता पिता का सम्मान किया गया। वहीं 9 महिलाओं को अलग अलग क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति सम्मान सृजन सम्मान से सम्मानित किया गया विगत 7 वर्षों से यह आयोजन किया जा रहा है। वृंदावन हाल सभागार में सम्पन्न हुए इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पद्मश्री फूलबासन यादव, अध्यक्षता ललिता मेहर डीएसपी महिला थाना, विशिष्ट अतिथि संगीता शाह प्रसिद्ध उद्योगपति उपस्थित थी। 101 बेटियों के माता पिता को सम्मानपत्र और बच्ची के लालन पालन की वस्तुएं फ्रॉक, साबुन, पावडर, खिलौने, बच्चो की मच्छर दानी और अन्य वस्तुए भेंट स्वरुप दी गई।

संस्था नवसृजन के प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा ने बताया कि बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने सस्था पिछले 7 वर्षों से यह आयोजन करती आ रही है जिसमे अब तक हजारों परिवारों को इस आयोजन के अन्तर्गत सम्मानित किया जा चुका है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पदम श्री फूलबासन यादव ने आयोजन की तारीफ करते हुए ऐसे आयोजन को प्रत्येक शहर में किया जाना चाहिए कहा, अपने संघर्ष के दिनो को याद करते हुए उन्होंने बकरी चराने से लेकर कौन बनेगा करोड़पति तक का सफर और महिला स्वसहायता समूह में 2 लाख महिलाओं को जोड़कर कार्य करना और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने पर शसक्त महिला के रूप में ऐसे ही कार्य करने की बात कही। डीएसपी ललिता मेहर ने छोटे से गांव से निकलकर शहर तक और पुलिस के उच्च विभाग तक के सफर की संघर्ष गाथा बताई। 6 माह से भी कम उम्र की 101 बेटियो की किलकारी से सभागार गुंजायमान था जिसमे 2 दिन से लेकर 6 माह तक की बेटियां नवरात्र में माता स्वरूप में उपस्थित थी।

केंद्र एवं राज्य शासन की योजनाओं को महिला बाल विकास की अधिकारी सपना ठाकुर द्वारा बताया गया। डा रश्मि चावरे आहार विशेषज्ञ ने आहार और पोषण सम्बंधित जानकारी देते हुए कहा कि बच्चे के जन्म के बाद अक्सर माँ अपने आहार को लेकर उतनी गम्भीर नही रहती। उन्होंने आहार पोषण को लेकर लापरवाही न बरतने, खान पान पर विशेष गौर करने की बात कही। 9 महिलाओं को अलग अलग क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति सम्मान सृजन सम्मान से सम्मानित किया गया जिसमें जिसमे अलग अलग क्षेत्र से कृति अग्रवाल व्यवसाय, संध्या शर्मा विधि, श्रुति सिंह पुलिस सेवा, स्वप्निल कर्महे कला, डा संध्या गुप्ता शिक्षा, याशी जैन साहस, रिंकी अरोरा स्वास्थ्य, मधुमिता पाल पत्रकारिता, भारती मोदी समाज सेवा, मधु यादव को शिक्षा सम्मान से सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम का संचालन देवाशीष मुखर्जी डा प्रीति सतपथी कांतिलाल जैन ने किया आयोजन में प्रमुख रूप से संस्था नवसृजन मंच के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा डॉ देवाशीष मुखर्जी कांतिलाल जैन किशोर महानंद सुनीता चंसोरिया, पदमा शर्मा, डॉ रश्मि चावरे, विनय शर्मा, सविता गुप्ता, मनीषा बघेल, प्रमिला शर्मा, सौरभ कोतु, मखमूर खान, सिद्धांत शर्मा, कमलेश कौर चावला सहित अन्य प्रमुखजन उपस्थित रहे।

विश्व रंगमंच दिवस पर लोक गायिका जयंती यादव सम्मानित

रायपुर। विश्व रंगमंच दिवस पर छत्तीसगढ़ राज्य शासन की ओर से लोक कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए देय सर्वोच्च पुरस्कार दाऊ मंदराजी से विभूषित लोक गायिका जयंती यादव का सम्मान छत्तीस छटा और पेड़ प्रहरी संस्थान के संचालक श्री विजय मिश्रा अमित सहित अन्य सदस्यों ने किया। जयंती विगत पांच दशक से छत्तीसगढ़ की शीर्ष संस्था चंदैनी गोंदा, सोनहा बिहान, नवा बिहान, दौना पान के अलावा आकाशवाणी के माध्यम से छत्तीसगढ़ी लोक गीतों, पारंपरिक रीति-रिवाजों को पुनर्जीवित प्रतिष्ठित करने में उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं। विश्व रंगमंच दिवस पर वरिष्ठ लोक - हिंदी रंगकर्मी श्री विजय मिश्रा सहित कपिल सोनी,अभिजीत शर्मा, गुलाल साहू,राधिका वर्मा,संजय यादव ,घासीदास जोशी आदि ने जयंती जी के गीतों और उनकी कला यात्रा अनुभव- स्मरण को सुना। उन्होंने कला यात्रा में कठोर अभ्यास को ही सफलता का मंत्र कहा। इस अवसर पर विजय मिश्रा ने बताया कि श्रीमति यादव के पचास वर्ष पूर्व गाए अनेक गाने बेहद लोकप्रिय हैं। आज भी आकाशवाणी या अन्य माध्यम से उनके गीतों को सुनना मनभावन होता है।

घायल बाघ का सफल रेस्क्यू,दो लोगों की ले चुका है जान

कुमकी हाथी और विशेषज्ञों की मदद से बाघ को ट्रैंकुलाइज कर सफलतापूर्वक रेस्क्यू

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के कालामांजन में मंगलवार सुबह घायल बाघ का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। बाघ ने 3 लोगों पर हमला कर दिया था, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई थी और एक युवक घायल हुआ था। अब बाघ के पकड़ लिए जाने से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। बाघ को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में बंद कर लिया गया है। कुमकी हाथी और विशेषज्ञों की मदद से बाघ को ट्रैंकुलाइज कर सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। प्राथमिक इलाज के बाद उसे ट्रक से मंगलवार देर रात तक रायपुर जंगल सफारी लाया जाएगा। यहां उसका बेहतर इलाज हो सकेगा। घायल बाघ को रेस्क्यू करने के लिए कुमकी हाथी और जेसीबी मशीन की मदद ली गई थी। पेड़ पर चढ़कर भी उसे काबू में करने की कोशिश की गई।

सीसीएफ सरगुजा नावेद सुजाउद्दीन ने बताया कि बाघ घायल है। सोमवार को बचने की कोशिश में ग्रामीणों ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। बाघ के सिर पर चोट है। उन्होंने कहा कि घायल बाघ काफी अंदर छिपकर बैठा हुआ था। कुमकी हाथी, डॉक्टरों और एक्सपर्ट की टीम की मदद से बाघ को ट्रैंकुलाइज किया गया है। उसे प्राथमिक चिकित्सा दी गई है। बेहतर इलाज के लिए जंगल सफारी भेजा जाएगा। बेहोश होने के बाद बाघ को स्ट्रेचर पर लिटाकर बाहर निकाला गया। इसके बाद उसे पिंजरे में बंद किया गया है। वहीं बाघ को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। बाघ का रेस्क्यू करने के बाद वन विभाग की टीम ने भी राहत की सांस ली है। कालामांजन गांव में रेस्क्यू के लिए बिलासपुर से स्पेशल टीम के साथ तमोर पिंगला से प्रशिक्षित कुमकी हाथियों को लाया गया था। इसी हाथी पर बैठकर वन विभाग की टीम जंगल के अंदर तक पहुंची थी।

गौरतलब है कि इस बाघ ने सोमवार को सूरजपुर जिले के कालामांजन गांव में 3 लोगों पर हमला कर दिया था। हमला करने के बाद उसने एक युवक को तो अपने पंजे में दबाए रखा, जिसके चलते मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया था। वहीं मृतक के साथ मौजूद 2 अन्य युवकों ने बाघ पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिसमें बाघ भी जख्मी हो गया। बाद में घायल कैलाश और राय सिंह को अस्पताल लाया गया, जहां एक और युवक की मौत हो गई थी। मामला ओडगी क्षेत्र का है।

सूरजपुर जिले के कालामांजन का रहने वाला समय लाल (32), कैलाश सिंह (35) और राय सिंह (30) सोमवार सुबह पास के जंगल में लकड़ी बीनने गए थे। सुबह 6 से 6.30 बजे के करीब अचानक से वहां पर टाइगर आ गया। उसने तीनों पर हमला कर दिया। बाघ ने सबसे पहले समय लाल को पंजे में दबा लिया था। उसके साथियों ने उसे छुड़ाने का प्रयास किया तो कैलाश के शरीर से मांस नोच लिया। ये देख कैलाश और राय सिंह ने कुल्हाड़ी से बाघ पर हमला किया। बाघ घायल भी हुआ, पर उसने कैलाश और समय लाल पर हमला करना नहीं छोड़ा।

छत्तीसगढ़ में फिर पहुंची ईडी

सीएम भूपेश ने कहा-अमित शाह के शब्दों में क्रोनोलॉजी समझिए

रायपुर। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल चल रहा है, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय श्च्च की छापेमार कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार तड़के सुबह ईडी ने एक बार फिर दबिश दी है। ईडी की टीम नेताओं के अलावा कई कारोबारियों के घर पहुंची है। महासमुंद विधायक व संसदीय सचिव विनोद सेवन लाल चंद्राकर के घर दो गाड़ियों में सवार होकर ईडी के अफसर पहुंचे हैं। कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के गोरे परिसर, सिविल लाइन स्थित ऑफिस में भी ईडी की टीम पहुंची है। कुछ कारोबारियों के घर भी ईडी की छापामार कार्रवाई चल रही है। रायपुर समेत बिलासपुर, रायगढ़ और भिलाई में भी ईडी की कार्रवाई की सूचना है।जमीन कारोबारियों के घर भी ईडी- छत्तीसगढ़ में लंबे समय से ईडी के अफसर जमे हुए हैं। प्रदेश में मनी लॉन्ड्रिंग और कोल ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े मामलों को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है। कुछ अफसर और कारोबारी इस मामले में जेल में है। कांग्रेस के कई नेताओं पर भी ईडी की नजर है। इस बार ईडी ने महासमुंद विधायक के अलावा जमीन से जुड़े कारोबारियों के घर भी दबिश दी है। रायपुर के शक्ति नगर में कारोबारी कमल सारडा के घर और जमीन से जुड़े कारोबारी सुरेश बांधे के घर ईडी पहुंची है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं।

भिलाई में जनसंपर्क आयुक्त आईपीएस दीपांशु काबरा के घर भी ईडी ने दबिश दी है। भिलाई स्थित उनके निवास में ईडी के अफसर पहुंचे हुए हैं। दीपांशु काबरा के पास परिवहन विभाग में एडिशनल कमिश्नर का प्रभार भी है। दीपांशु काबरा 1997 बैंच के आईपीएस अफसर हैं

बिलासपुर में केके श्रीवास्तव के घर ईडी की दबिश

बिलासपुर के कई स्थानों पर ईडी ने सोमवार को छापेमार कार्रवाई की। दर्जनभर गाड़ियों में भरकर अधिकारियों की फौज जांच करने पहुंची थी। बिलासपुर के भारती नगर में रहने वाले केके श्रीवास्तव के घर ईडी की टीम जांच करने पहुंची। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों सहित पुलिस की टीम घर के दरवाजे पर मौजूद रही। वहां, न किसी को अंदर आने दिया जा रहा था और ना किसी को बाहर जाने दिया जा रहा था।अधिकारियों की फौज यहां पूरे दिन कागजातों की छानबीन करती रही

ईडी पर भूपेश बघेल का निशाना

छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा आज छत्तीसगढ़ में फिर ईडी आई है। उद्योगपति, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, अधिकारी, नेता, किसान कोई ऐसा नहीं बचा है जिनके घर ईडी का छापा ना पड़ा हो। मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में कभी ईडी कार्रवाई नहीं करती, वहां ईडी का ऑफिस ही नहीं है। महाराष्ट्र में जब तक उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तब तक ईडी, सीबीआई सक्रिय थी। जैसे ही खरीद फरोख्त हुआ, सरकार बदली, ईडी का वहां कोई काम नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार के इशारे पर सब काम हो रहा है। ईडी निष्पक्ष होना चाहिए। अडानी के घर में ईडी छापा नहीं मारती, नान और चिटफंड कंपनी के खिलाफ ईडी कार्रवाई नहीं करती। महादेव एप पर भी कार्रवाई नहीं हो रही। क्योंकि भाजपा शासित राज्यों के नाम उससे जुड़े हैं। सीएम ने कहा अमित शाह के शब्दों में क्रोनोलॉजी समझिए। जैसे ही राहुल गांधी ने लोकसभा में सवाल उठाया। रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने भाषण दिया। उसके बाद लोकसभा बाधित, सत्ता पक्ष ने चलने ही नहीं दिया। गुजरात के कोर्ट में कर्नाटक के मामले में मानहानि के मामले में शिकायत हुई। शिकायतकर्ता ने अपने ही केस में हाईकोर्ट में स्टे ले लिया। 7 फरवरी को जैसे ही राहुल गांधी ने ये बात कही। 16 फरवरी को हाईकोर्ट में स्टे विकेट हो गया। 16 मार्च तक सुनवाई हो गई। 23 मार्च तक फैसला हो गया। 24 मार्च को सदस्यता रद्द कर दी गई। अडानी के खिलाफ ये सब क्यों नहीं हो रहा है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम पर रमन सिंह का पलटवारकांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवशेन से पहले पड़ा था छापा: कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से ऐन पहले ईडी ने कांग्रेस नेताओं के घर दबिश दी थी। इस दौरान कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया था। ईडी ने श्रम विभाग के अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, बिलाईगढ़ विधायक चंद्रदेव राय, कांग्रेस प्रदेश कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल, कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह, कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन और कांग्रेस के युवा नेता विनोद तिवारी के घर दबिश दी थी। उसके बाद से लगातार इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि छापे और पूछताछ के बाद किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। ईडी की उस छापेमारी के बाद आज फिर कार्रवाई की जा रही है।

ओबीसी के नाम पर भाजपा बांटने का कर रही प्रयास: शैलजा

रायपुर। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा मंगलवार को दो दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचीं। शाम को कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लेंगी तो वहीं बुधवार को एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित करेंगी।

दोनों कार्यक्रम कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में रखे गए हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कुमारी शैलजा ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी के मामले को लेकर भी केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी के बयान को भाजपा ओबीसी का अपमान कह रही है। इस पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री ओबीसी से हैं। राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री ओबीसी से हैं। यहां मैं फिर कहूंगी कि यह उनकी सोच है। हमारे देश को, समाज को हर तरह से बांटने का प्रयास करते हैं, चाहे धार्मिक रूप से, चाहे जाति के रूप से। जब इन्हें कुछ नहीं मिलता तो यह समाज को बांटने की बात करते हैं। ओबीसी का न मुद्दा था और न यह मुद्दा है। भाजपा इसे जितना भी मुद्दा बनाना चाहे, लेकिन यह मुद्दा नहीं होगा और न यहां की जनता ऐसे मुद्दे को एक्सेप्ट करेगी। राहुल गांधी को घर खाली करने के नोटिस पर कुमारी शैलजा ने कहा आपने देखा है कि किस तरह बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार, हमारे नेताओं और शीर्ष नेताओं को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोगों की आवाज को कैसे दबा सकते हैं। हमारा लोकतंत्र में विश्वास है। राहुल गांधी ने हमेशा लोगों के आवाज को, युवाओं की आवाज को उठाया है और वह आवाज कभी दब नहीं सकती। आप यह देख सकते हैं कि किस हद तक किस निम्न स्तर तक यह लोग जा सकते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ सजिश रची गई और उनका घर छुड़वाने की बात वह कर रहे हैं। इससे उनकी ओछी सोच नजर आ रही है। राहुल गांधी मामले पर आगे की रणनीति पर कुमारी शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है, राज्य में जो हो रहा है, उससे यहां के लोगों में भी काफी गुस्सा है। यह सारी चीजें एक प्लानिंग से हो रही है। चाहे वह राहुल गांधी के साथ हो या यहां के लोग इसके साथ। यहां की जनता चुप नहीं बैठेगी और कांग्रेस पार्टी भी चुप नहीं बैठेगी। चाहे संसद में हो, विधानसभा में हो या सड़क पर, हम इस संघर्ष को हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं। विधानसभा चुनाव में यहां के लोग भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। यह न्यायपालिका का रोल है, बीजेपी का नहीं, भाजपा के इस बयान पर कुमारी शैलजा ने पलटवार करते हुए कहा कि यह सारी बातें पहले भी कही जा चुकी है कि, किस तरीके से यह पूरा चक्रव्यूह रचा गया है। उसके बावजूद हम यह कहते हैं कि हमारा विश्वास है देश की न्यायपालिका पर और जो कानूनी लड़ाई है वह हम कानूनी रूप से लड़ते रहेंगे। लेकिन जो सारा प्लॉट है वह सारी दुनिया के सामने है।

बाबू भैया की कलम से

तमिलनाडु से समझें, कट्टरवादी सोच देश का कितना नुकसान करेगी

एक फेक खबर के गंभीर परिणाम ने हरेक राष्ट्रभक्त व्यक्ति को गंभीरता से सोचने को मजबूर कर दिया है। घटना पिछले दिनों एक सिरफिरे की एक अदद पोस्ट की है। जिसमें उसने अपने पागलपन के कारण एक राज्य को भारी नुकसान पहुंचाने का काम किया। पोस्ट तमिलनाडु में काम करने आये बिहारी मजदूरों के बारे में थी। उसने शूट करके बनाई एक फेक वीडियो पोस्ट कर दी , जिसमें लिखा कि चेन्नई में बिहारी कामगारों को पीटा जा रहा है,मारा जा रहा है। मजदूरों को जान के लाले पड़ गये हैं। मजदूर पलायन कर रहे हैं। उनकी जान खतरे में है। इस खबर ने देश के साथ दुनिया को भी सोचने को मजबूर किया। नफरत की कट्टर राजनीति से उपजी यह पोस्ट राज्य और देश को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। शायद उस पोस्ट करने वाले को पता था या नहीं कह नहीं सकते,लेकिन यह तो माना जाना चाहिए कि यह कट्टरवाद का पागलपंथ ही है। चर्चा है कि दक्षिण में हिंदी भाषी लोगों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। हिन्दी भाषियों को वहां अनेक प्रकार का अपमान सहना पड़ता है।दक्षिण भाषी लोग देश के हिंदी भाषी को अपना नहीं मानते। चेन्नई में किसी से कुछ पूछो तो या तो अनमने भाव से जवाब देंगे या अनसुनी करके आगे बढ़ कर एक प्रकार से हिंदी भाषियों का अपमान ही करते हैं। अनुभव करने वाले अनेक लोगों ने यह बात बताई ,कि वहां बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खैर ये तो हुई सुनी सुनाई बातों की चर्चा। असल मुद्दा ये है कि जो फेक वीडियो जारी किया गया उससे राज्य का किस प्रकार नुकसान हुआ। आज के अखबार में प्रकाशित समाचार देख कर यह आसानी से समझा जा सकता है। परम्परागत ढंग से हर साल लाखों की संख्या में देश के अन्य भागों से हिंदी भाषी मजदूर देश भर के विभिन्न राज्यों में कमाने खाने जाते हैं। खास कर बिहारी व छत्तीसगढ़िया मजदूरों की भारी मांग है। क्योंकि ये लोग ज्यादा मेहनत कश होते हैं। छत्तीसगढ़िया का तो सीधे सादे व ईमानदारी में पहला नम्बर माना जाता है। बिहारी मजदूर को कड़ी मेहनत में माहिरता हासिल है। उस वीडियो के प्रभाव में आकर होली दीवाली के समय अपने गांव लौट कर त्योहार के बाद सब फिर से वापस अपने काम पर पहुंचने लगते हैं। इस बार ऐसा नहीं हुआ। हुआ यह कि वीडियो के प्रचार ने शायद मजदूरों को डरा दिया है। लगभग दो लाख प्रवासी मजदूर काम पर नहीं लौटे। चेन्नई के हवाले से छपी खबर में लिखा है कि राज्य के कोयम्बटूर व त्रिपुर की अनेक गारमेंट फैक्टरियां मजदूरों के बिना सूनी पड़ी हैं। गारमेंट के साथ राज्य की अनेक मैन्युफैक्करिंग यूनिट्स के हब भी बंद पड गये हैं। लगभग 50 हजार छोटी बड़ी फैक्टरियों के उत्पादन पर भारी असर पड़ा है।चेन्नई की होटल इंडस्ट्रीज में भी भारी प्रभाव पड़ा है। 10 हजार के करीब होटल पर असर पड़ा है। गारमेंट के क्षेत्र में इन मजदूरों की उपस्थिति 60 प्रतिशत होती है। वहीं होटल,रेस्तरां,कैफ़े व बेकरी के बिजनेस में ढाई लाख प्रवासी मजदूर काम करते हैं। फेक वीडियों में दिखाए गए मजदूरों पर हमले के दृश्य मजदूरों को आज भी भयभीत कर रहे हैं। हालांकि शासन ने अनेक सकारात्मक प्रयास इस दिशा में किये हैं। प्रभावित कंपनियों के मानव संसाधन विभाग के अधिकारी फ़ोन करके मजदूरों को सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं ,लेकिन मजदूरों का भरोसा नहीं जम रहा है। खास कर उत्तर भारतीय मजदूर वापसी से कतरा रहे हैं। मालिकों का कहना है कि उत्पादन जारी रखना मुश्किल हो रहा है।उनका यह भी कहना है कि प्रवासी मजदूरों के बिना उत्पादन की कल्पना भी नहीं की जा सकती । इधर मजदूर चेन्नई छोड़ केरल ,कर्नाटक का रुख कर रहे हैं। स्थिति विषम हो रही है। चेन्नई में उड़ीसा,उत्तर प्रदेश, झारखंड व पश्चिम बंगाल के मजदूर कमाने जाते थे। सभी की रोजीरोटी का नुकसान हो रहा है। हरेक को सोचना होगा कि मात्र एक व्यक्ति की कट्टरवादी सोच राज्य व देश को कितनी भीतरी व गहरी चोट पहुंचा सकती है। यह हर उस संस्था को सोचना चाहिए जो देश में नफरत व जातिवादी तथा धार्मिक कट्टरता की सोच से काम कर रही हैं। इस घटना ने तो यही सीख दी है। कोई माने या ना माने। कहा भी गया है ,कि नहीं मानेंगें तो होई है वही जो..?

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

किसानों की 40,625 करोड़ की बकाया राशि कब देगी: अरुण साव

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ताजा घोषणा किसानों के साथ एक और छलावा है। श्री साव ने कहा पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान श्रीमान राहुल गांधी ने पूरे छत्तीसगढ़ में घूम घूम कर यह कहा था कि वह धान खरीदी की लिमिट को खत्म कर देंगे और अगर कांग्रेस मानती है कि प्रति एकड़ धान की उत्पादकता 20 क्विंटल है तो यह बताएं कि किसानों को 40,625 करोड़ का बकाया भुगतान कब करेगी? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा राज्य में पंजीकृत किसानों की संख्या के आधार पर औसत लगभग 65 लाख एकड़ से प्रति वर्ष धान की खरीद हो रही है 5 वर्ष में कुल लगभग 3 करोड़ 25 लाख एकड़ से घान खरीदी हुई ।कांग्रेस सरकार यदि 15 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल खरीदी करती तो 5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से 16 करोड़ 25 लाख क्विंटल सरकार को और किसानों से खरीदना होता और 2500 रु प्रति क्विंटल के हिसाब से यह राशि 40 हजार 625 करोड़ होती है जो कांग्रेस सरकार को किसानों को देना चाहिए अगर वह उत्पादकता को 20 क्विंटल प्रति एकड़ मानते है।

कांग्रेस का अलोकतांत्रिक आचरण आपातकाल की याद ताजा कर रहा-भाजपा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध सूरत कोर्ट द्वारा मोदी सरनेम को चोर बताने वाली टिप्पणी के लिए मानहानि का दोष सिद्ध होने पर 2 वर्ष की सजा के फैसले और इस कारण संसद की सदस्यता रद्द किए जाने पर कांग्रेस के लोग जिस तरह का अमर्यादित और अलोकतांत्रिक आचरण कर रहे हैं, उससे सन 1975 के आपातकाल की याद ताजा हो चली है। श्री चौधरी ने कहा कि सन 75 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शासकीय मशीनरी के दुरुपयोग का दोष सिद्ध होने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया था। उस समय भी इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने न्यायालय का निर्णय मानने के बजाय देश पर आपातकाल थोप दिया था और पूरे देश को जेल बनाकर रख दिया था। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री चौधरी ने कहा कि एक बार फिर पिछड़ा वर्ग के अपमान के कारण राहुल गांधी को हुई सजा और उसके बाद संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संसद सदस्यता खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के नेता न्यायपालिका और संविधान का सम्मान करने के बजाय छत्तीसगढ़ में आपातकाल के हालात बनाने पर तुले हुए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि पिछड़ा वर्ग का अपमान करने और मोदी सरनेम को चोर से जोड़ने के कारण मानहानि का दोष सिद्ध होने पर राहुल गांधी को हुई सजा का सत्य और तथ्य छिपाकर कांग्रेस के लोग अपने बयानों से राजनीतिक विषवमन कर एक तो न्यायालय और संविधान का खुलेआम अपमान करने की धृष्टता कर रहे हैं।

भाजपा किसानों से 20 क्विंटल धान खरीदने के निर्णय का विरोध क्यों कर रही है?

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि आखिर भाजपा भूपेश सरकार के द्वारा किसानों से 20 क्विंटल धान खरीदने के निर्णय का विरोध क्यों कर रही है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने खुशहाल बनाने का कार्य कर रही है। जिसका विरोध कर भाजपा अपने किसान विरोधी मसूबे को पूरा कर रही है। 2013 के दौरान भाजपा ने प्रदेश के किसानों से एक-एक दाना धान खरीदने का वादा किया था लेकिन वादा पूरा नही किया। किसानों को धोखा दिया। प्रदेश की कांग्रेस सरकार अगामी खरीफ सीजन में लगभग 2800 रु. की दर से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने जा रही है। भाजपा ने 20 क्विंटल धान खरीदी का विरोध कर अपने किसान विरोधी मनसूबे को पूरा करना चाहती है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के डीएनए में है किसानों का विरोध करना यही कारण है जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों को वादा अनुसार धान की कीमत 2500 रु. प्रति क्विंटल दिया तब केंद्र की भाजपा सरकार ने विरोध किया और नियम शर्ते लगाकर किसानों को एकमुश्त मिलने वाली 2500 रु. राशि देने पर अवरोध उतपन्न किया।

बेरोजगारी भत्ता के निर्णय से भाजपा घबराई - कांग्रेस

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा भूपेश सरकार द्वारा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के निर्णय से घबरा गयी है तथा अनर्गल बयान बाजी में उतर आई है। 15 साल तक युवाओं का शोषण करने वाली भाजपा किस मुंह से बेरोजगारी भत्ता देने बनाए गए नियमों पर सवाल उठा रही है? भाजपा को बेरोजगारी भत्ता पर सवाल पूछने से पहले दो करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने के अपने वादा का विश्लेषण करना चाहिये और प्रदेश के युवाओं को बताएं की नरेंद्र मोदी की सरकार ने 9 साल में प्रदेश के कितने युवाओं को रोजगार दिया है? दो करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से प्रदेश के 43 लाख युवाओ को रोजगार मिलना था नरेंद्र मोदी की सरकार प्रतिवर्ष दो करोड रोजगार देने में असफल रही हैं और उल्टा मोदी सरकार की गलतियों नासमझी के चलते अब तक 23 करोड़ हाथों से रोजगार छीना जा चुका है। यानी प्रति वर्ष लगभग 2 करोड़ 5 लाख 55 हजार 555 हाथों से रोजगार छीना गया है। मोदी सरकार की तरह ही पूर्व की रमन सरकार ने भी प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा और छल किया था 2003 में 12वीं पास युवाओं को 500 रू. प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कर वादा पूरा नहीं किया था और उल्टा सरकारी नौकरी को आउटसोर्सिंग के माध्यम से बेचकर प्रदेश के युवाओं को हक अधिकार से वंचित किया था। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता देने का वादा नहीं किया था।

राजस्थान सरकार के फैसले का छत्तीसगढ़ में विरोध

रायपुर। आई एम ए रायपुर के सदस्यों ने राजस्थान सरकार द्वारा लाए गए राइट टू हेल्थ कानून के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. डॉक्टर काली पट्टी बांधकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे. राजस्थान सरकार के नाम कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे को सौपा ज्ञापन. राजस्थान सरकार द्वारा लाए गए 2023 के राइट टू हेल्थ बिल का विरोध किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने इस बिल को गैर कानूनी बिल बताया है. राइट टू हेल्थ बिल को अगले विचार-विमर्श तक लागू होने से रोकने की अपील की है। ज्ञापन के माध्यम से जानकारी देते हुए डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि पूरे भारतवर्ष का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत समुदाय राजस्थान में पास हुए राइट टू हेल्थ बिल 2023 को लेकर चिंतित है. और बिना विचार-विमर्श जल्दबाजी में लाए गए इस गैरकानूनी बिल का प्रतिरोध करता है। इस बिल में सभी मरीजों के लिए प्राइवेट अस्पताल में आपातकालीन सेवाएं सुनिश्चित करने का निश्चय व्यक्त किया गया है, लेकिन इस बिल में आपातकालीन स्थिति को चिकित्सकीय दृष्टि से परिभाषित नहीं किया गया है. इस बिल को सरकारी अस्पतालों और संस्थानों के लिए प्रारंभिक तौर पर लागू किया जाए. कोई भी जनकल्याणकारी सरकार किसी भी मॉडल को सफल होने के लिए अपने अस्पतालों में लागू करना पसंद करती है. सीधे-सीधे निजी स्वास्थ्य क्षेत्र में इसको लागू करने से विरोध और संशय की स्थिति सामने आना कि सम्भावना है। कानूनी दृष्टि से ना केवल यह बिल निजी क्षेत्र के लिए आक्रामक बताया जा रहा है।

जी-20: सतत जलवायु के लिए जल संरक्षण जरूरी-पंकज कुमार

रायपुर। भारत ने 1 दिसंबर, 2022 को इंडोनेशिया से जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण की। जी-20 नेतृत्व, देश को ग्लोबल वार्मिंग, भोजन और ऊर्जा की कमी, आतंकवाद, भू-राजनीतिक संघर्ष और डिजिटल अंतर को कम करने समेत विभिन्न आकस्मिक स्थितियों से मुकाबला करने के लिए दुनिया को भारत के प्रयास तथा वर्तमान स्थिति (इंडिया स्टोरी) को सामने रखने का अवसर प्रदान करता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत की जी-20 अध्यक्षता; पिछली 17 अध्यक्षता के कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के आधार पर आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस वर्ष की जी-20 थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य; भारत के वसुधैव कुटुम्बकम (विश्व एक परिवार है) के अंतर्निहित दर्शन को पूरी तरह से व्यक्त करती है। यह दर्शन भारत के जी-20 नेतृत्व का मार्गदर्शन करेगा। पहली जी-20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक एक सकारात्मक परिणाम के साथ संपन्न हुई, जिसमें सभी जी-20 देशों ने भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित विषयों पर अपना समर्थन व्यक्त किया। निम्न उर्वरता भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने, समुद्र-तटीय क्षेत्रों में नीली अर्थव्यवस्था के जरिये सतत विकास को बढ़ावा देने, जैव विविधता को बढ़ाने, जंगल की आग और समुद्री कचरे को रोकने, चक्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने आदि विषयों पर हुई गहन चर्चा ने दूसरे शिखर सम्मेलन में अधिक सकारात्मक व दृष्टिगत विचार-विमर्श के लिए मंच तैयार किया है।

केलो बांध में पानी भरा, लेकिन गांवों तक पहुंचने नहर ही पूरी नहीं

सर्वाधिक 75 फीसदी भरा है केलो डेम, नहरों का काम पूरा हो तो गांवों तक पहुंचेगा पानी

रायगढ़। केलो बांध का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया था कि बारिश के प्राकृतिक जल को यहां स्टोर किया जा सके और आवश्यकतानुसार नहरों के माध्यम से गांवों तक पहुंचाया जा सके। केलो बांध में आज जिले के दूसरे बांधों के मुकाबले सर्वाधिक 75 फीसदी पानी भरा है किंतु नहरों का काम पूरा नहीं हो पाने के कारण बहुत से गांवों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। सिंचाई विभाग से मिले आंकड़ों के आधार पर जिले के बांधों को देखे तो केडार बांध में 54.47 प्रतिशत, पुटका में 52.35 प्रतिशत और सारंगढ़ के किंकारी में 25.80 प्रतिशत और केलो बांध में 75.29 प्रतिशत पानी भरा हुआ है। इस लिहाज से अभी जिले में सबसे अधिक पानी केलो बांध में ही भंडारित है।

ईई केलो परियोजना श्री पी.आर.फुलेकर ने बताया कि केलो बांध की जल भंडारण क्षमता 61.95 मिलियन क्यूबिक मीटर है। वर्तमान में केलो में 46.64 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है। उन्होंने बताया कि केलो परियोजना में नहरों का काम 80 फीसदी हो चुका है। लेकिन 20 प्रतिशत नहरों का काम शेष होने के कारण कई गांवों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इनमें कई छोटे-छोटे पैच के काम शेष है। परियोजना में अब युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है जिससे नहर निर्माण का कार्य जल्द पूरा हो और लाभान्वित होने वाले गांवों तक पानी पहुंचे।

गौरतलब है कि परियोजना में कुल 313 किमी लंबाई के नहर बनाने है। जिसमें से 248 कि.मी. लंबाई की नहरें बनाई जा चुकी हैं। इसमें 1 मुख्य नहर के साथ 1 शाखा नहर, 7 वितरक नहर और 91 लघु नहरों का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें मुख्य नहर के 28.31 किमी और झारमुड़ा के 16.11 किमी शाखा नहर का काम पूरा किया जा चुका है। वहीं 68.60 किमी वितरक नहर और 135.50 किमी लघु नहरों का काम पूरा हो चुका है। शेष कार्य भी पूरा किया जा रहा है। परियोजना को दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना के पूरे होने से 175 गांवों के 22 हजार 810 हेक्टेयर को सिंचाई सुविधा मिलेगी। जिसमें रायगढ़ जिले के 167 गांवों की 21 हजार 596 हेक्टेयर और सक्ती जिले के 8 गांवों की 1 हजार 214 हेक्टेयर जमीन शामिल है। केलो वृहत परियोजना की शुरुआत 2009 में हुई थी। इसकी लागत 891 करोड़ रुपए है। इसमें केलो डैम के निर्माण के साथ ही मुख्य नहर, शाखा और वितरक नहरों का निर्माण शामिल है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.